वर्ष-11, अंक-6, मार्च-2026

मूल्य: ₹20

# वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

## विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया

# GANGA SAGAR ANAND & CO.

VIKAS ANAND

A Name that Inspires trust....
Make Savings a Habit
Rather that a chance

***Our Accomplishments :-***

**1st Platinum Club Member**
**CEO Club Member Shriram**
**Cot Member (HDFC LIFE)**
**MDRT Qualifier (LIC)**



## *Vikas Anand*

MBA.MDRT (USA)
(Insurance & Investment Consultant
AMFI Registered Mutual Fund Advisor

***Deals in :***

- Term Insurance
- Mutual Funds
- Health Insurance
- Systematic Investment Plan (SIP)
- Post Office Schemes
- Fixed Deposit
- LIC Authorised Premium Collection Center

*पॉलिसी लेने के बाद हमारा रिश्ता खत्म नहीं आरम्भ होता है। और रिश्ते ऐसे जो कभी समाप्त न हो। ऐसा दावा आपको मिल सकता है। सिर्फ एक ही जगह, सेवा एक आश्वासन है। आश्वासन भी ऐसा .... जो जिम्मेदारी से परिपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि एक बार जिम्मेदारी सौंपने की कृपा करें। हम आपकी आशा के अनुरूप खरे उतरेंगे।*

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE
HDFC Life
SHRIRAM Finance
LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

**बचत की आदत डालिए**
**भाग्य पर मत छोड़िए**

**SERVICE AT YOUR DOORSTEP**
**Vikas Anand S/o Ganga Sagar Anand**
R-15/25, Next DM Residence, Raj Nagar, Ghaziabad (U.P)
**Ph : 9810443447 / 0120-4109442**
E-mail : anandv127@gmail.com Website : wealthelite.in

Note : Please download Vikas Anand app to avail our services.
Available on Google Play Store as well as Apple App Store.

वर्ष- 11 अंक- 6

मार्च-2026



सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोड़ा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी



मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568



नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।


# अन्दर के पेजों में...





कवर स्टोरी पेज-28

खाकी का 'मानवीय' चेहरा और अनुशासन का 'मजबूत' स्तंभ: पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ — पेज 05



योगी आदित्यनाथ के 9 साल: राम मंदिर से काशी कॉरिडोर तक यूपी में सांस्कृतिक पुर्नजागरण — पेज 08



खाकी का 'संकल्प' और अपराधियों का 'काल' एडिशनल सीपी केशव कुमार चौधरी — पेज 14

दूरदृष्टि और विकास का संतुलन, आम बजट में भविष्य की झलक: एस.एन. सिंह — पेज 18

भारत में महिलाओं के प्रति बदलने लगा है नजरिया — पेज 46

वर्ल्ड कप-2026 ये 5 क्रिकेटर रहे हीरो — पेज 54



विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

# क्या पश्चिम एशिया का युद्ध खत्म कर देगा घर की गैस?

ललित कुमार
सम्पादक

पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से जैसे हालात बन गए हैं और जैसे-जैसे दिन लंबे खिंचते जा रहे हैं, उसके असर का दायरा भी बढ़ने लगा है। युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, उसके कारण वैसे देश भी बुरी तरह प्रभावित हो हैं, जो टकराव से दूर हैं। दरअसल, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद समूचा पश्चिम एशिया प्रभावित है और इसका खाड़ी देशों में तेल उत्पादन पर खासा असर पड़ा है। इस बीच ईरान ने जिस तरह होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित कर दिया है, उसके बाद उस मार्ग से होकर दुनिया के कई देशों में तेल की आपूर्ति भी रुक गई है। खासतौर पर भारत में तेल और गैस की दिक्कत जिस रूप में देखी जा रही है, वह कई स्तर पर चिंता पैदा करती है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा गया है कि देश के पास रणनीतिक और व्यावसायिक भंडार की पर्याप्त मात्रा मौजूद है और घरों तथा वाहनों के लिए इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। सरकार ने उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की गैरजरूरी जमाखोरी से बचने की अपील की है। विडंबना यह है कि एक ओर सरकार ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित बता रही है, दूसरी ओर देश के कई हिस्सों से बाजार में रसोई गैस के लिए अफरा-तफरी की खबरें आ रही हैं। सवाल है कि जब सरकार सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दे रही है, जमाखोरी न करने की हिदायत दे रही है, तब भी लोगों के बीच रसोई गैस की कमी होने की आशंका कैसे फैल गई। असल में जब ईरान ने होर्मुज समुद्री मार्ग को रोक दिया और उसका असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ने लगा, तब सरकार ने न केवल खाना पकाने के गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, बल्कि पच्चीस दिन के बाद ही नया सिलेंडर मिलने की शर्त लगा दी। शायद यही वजह है कि लोगों के बीच यह धारणा बनी कि आने वाले दिनों में रसोई गैस की किल्लत होने वाली है। इसी के बाद एहतियातन रसोई गैस के सिलेंडर लेने की एक तरह से होड़ मच गई, जिसका फायदा कालाबाजारी करने वालों ने उठाया और कई जगहों से ऊंची कीमतों पर सिलेंडर बेचे जाने की खबरें आईं। इसी तरह, बिजली से चलने वाले चूल्हों की बिक्री में खासा इजाफा देखा गया। अव्वल तो यह समझना मुश्किल है कि ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध और उसकी वजह से उपजने वाली स्थिति का अनुमान लगाने तथा उसी मुताबिक संकट का सामना करने की तैयारी करने के मामले में सरकार ने उदासीनता क्यों बरती। अब सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाने, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रसोई गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर लोग आशंकित हैं और कहीं इसके लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, तो कहीं ज्यादा पैसे चुकाने पर मजबूर हैं! अगर सरकार का कहना सही है कि रसोई गैस की कमी नहीं है, तो सबसे पहले उसे देश भर में रसोई गैस सिलेंडरों की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए और अफवाहों पर लगाम लगाना चाहिए। फिर इस अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी न हो, इसके लिए उसे जनजागरूकता फैलाने से लेकर कानूनी कार्रवाई के सभी उपाय अपनाने चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में किसी को अपने लिए मुनाफा कमाने का मौका बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

में तेल की आपूर्ति भी रुक गई है। खासतौर पर भारत में तेल और गैस की दिक्कत जिस रूप में देखी जा रही है, वह कई स्तर पर चिंता पैदा करती है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा गया है कि देश के पास रणनीतिक और व्यावसायिक भंडार की पर्याप्त मात्रा मौजूद है और घरों तथा वाहनों के लिए इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। सरकार ने उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की गैरजरूरी जमाखोरी से बचने की अपील की है।

## खाकी का 'मानवीय' चेहरा और अनुशासन का 'मजबूत' स्तंभः

# पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़

**जब खाकी के साथ 'विद्वता' और 'विनम्रता' का मेल होता है, तो समाज में सुरक्षा का एक नया विश्वास जन्म लेता है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के वर्तमान सारथी आईपीएस जे. रविंदर गौड़ (2005 बैच) इसी विश्वास के जीते-जागते प्रतीक हैं। 1 दिसंबर 1973 को तेलंगाना की मिट्टी में जन्मे और 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में परास्नातक करने वाले रविंदर गौड़ ने अपनी कार्यशैली से यह सिद्ध कर दिया है कि पुलिसिंग केवल डंडे के दम पर नहीं, बल्कि 'संवाद' और 'सिस्टम' के दम पर चलती है।**

ललित कुमार

### गाजियाबाद में 'गौड़' युगः थानों में चाय और तमीज का 'नया दौर'

पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालते ही जे. रविंदर गौड़ ने जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया, वह था 'शिष्टाचार संवाद नीति'। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि थाने आने वाला हर फरियादी सम्मान का हकदार है। थानों में अब 'तू-तड़ाक' की जगह सम्मानजनक संबोधन ने ले ली है। फरियादियों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब फरियादी को कागज के लिए भटकना नहीं पड़ता, FIR की कॉपी सम्मान के साथ घर पहुंचाई जा रही है। पूरे शहर को 2,131 बीट में बांटकर उन्होंने सुरक्षा को गली-मोहल्लों तक पहुंचा दिया है। अब हर सिपाही अपनी बीट का 'जिम्मेदार' है।

### विकास और विजनः 11 नए थानों की नींव

**गाजियाबाद** की बढ़ती आबादी और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए कमिश्नर गौड़ ने 11 नए थानों का प्रस्ताव देकर

भविष्य की सुरक्षित नींव रखी है। साहिबाबाद से लेकर राजनगर एक्सटेंशन तक, पुलिस की पहुंच को और अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए 'जोन-वार कार्यकाल' निश्चित कर पारदर्शिता की नई मिसाल पेश की है।

## मिशन शक्तिः नारी शक्ति को मिली नई उड़ान

कमिश्नर गौड़ के नेतृत्व में 'मिशन शक्ति 0.5' ने गाजियाबाद की सड़कों पर एक नई ऊर्जा भरी है। जब पुलिस लाइन से सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली निकली, तो वह केवल एक मार्च नहीं था, बल्कि अपराधियों के लिए चेतावनी और महिलाओं के लिए सुरक्षा का संकल्प था।

## अनुभव की आंच पर तपा व्यक्तित्व

आगरा पुलिस कमिश्नरेट हो या गोरखपुर रेंज, मेरठ से लेकर लखनऊ तक, जे. रविंदर गौड़ का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। आगरा में जब पुलिस 'जगदीशपुरा कांड' के विवादों में घिरी थी, तब उन्होंने अपनी निष्पक्ष जांच से विभाग की साख बचाई। जीवन में आई चुनौतियों और 2017 जैसी कठिन परिस्थितियों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया, क्योंकि उनका मानना है कि 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।'

## ड्यूटी की वो 'अनकही' बातः जो उन्हें खास बनाती है

जे. रविंदर गौड़ अक्सर अपने साथियों से कहते हैं कि 'वर्दी का असली गौरव तब है, जब कोई गरीब व्यक्ति आपसे बात करते समय डरे नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस करे' वह ड्यूटी के दौरान अक्सर उन क्षणों को याद करते हैं जब एक आम नागरिक की आंखों में संतुष्टि के आंसू दिखते हैं। उनके लिए पुलिसिंग एक नौकरी नहीं, बल्कि सेवा का एक 'पवित्र अनुष्ठान' है।

## स्मार्ट सिटी और स्वच्छता का संकल्प

पुलिसिंग के साथ-साथ कमिश्नर गौड़ नगर निगम और प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। प्लास्टिक के खिलाफ अभियान हो या '3R' (Reduce, Reuse, Recycle) के तहत कांच के कचरे से सजावट, उनका विजन गाजियाबाद को एक 'स्मार्ट और क्लीन सिटी' बनाने का है।

अनुभव का तर्जुबा और युवा जोश का मेल हैं जे. रविंदर गौड़। गाजियाबाद की जनता आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि कमान एक ऐसे अधिकारी के हाथ में है जो कानून की भाषा भी जानता है और जनता के दर्द की भाषा भी।

# मजबूत सेना, स्वदेशी हथियार और नई युद्ध तकनीक, यही है मोदी सरकार की जबरदस्त सामरिक रणनीति

**पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हथियार आयातक देश की छवि से बाहर निकलकर रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत से लगभग 3800 करोड़ रुपये की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है।**

प्रदीप कुमार शर्मा

साल 2026 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, चीन की आक्रामक सैन्य विस्तार नीति, हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीमा क्षेत्रों में लगातार तनाव ने भारत को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए मजबूर किया है। इसी पृष्ठभूमि में मोदी सरकार ने वर्ष 2026 में ऐसी सामरिक रणनीति अपनाई है जिसका मूल उद्देश्य है सैन्य शक्ति का तीव्र आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन का विस्फोटक विस्तार, नई युद्ध तकनीकों में निर्णायक बढ़त और वैश्विक रक्षा कूटनीति का विस्तार।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे पहली और सबसे स्पष्ट प्राथमिकता है रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 7.85 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो प्रतिशत है और केंद्र सरकार के कुल

खर्च का लगभग 14.67 प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्र को जाता है। इस बजट में 2.19 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं ताकि सेना को अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान, आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बी, ड्रोन और स्मार्ट हथियारों से लैस किया जा सके। मोदी सरकार की दूसरी निर्णायक रणनीति है सैन्य आधुनिकीकरण को तेज करना। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि भारत को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी होगी। इसी रणनीति के तहत भारत ने नौसेना के लिए 26 आधुनिक राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का लगभग 7.4 अरब डॉलर का समझौता किया है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति और मजबूत होगी।

इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए नए लड़ाकू स्क्वॉड्रन, आधुनिक मिसाइल प्रणाली और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियारों पर तेजी से काम चल रहा है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चीन और पाकिस्तान दोनों से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में उठाया गया है। तीसरी बड़ी प्राथमिकता है आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग का निर्माण। वर्ष 2026 के रक्षा बजट में पूंजीगत खरीद का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ है कि लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये भारतीय कंपनियों और रक्षा निर्माण इकाइयों को मिलेंगे। इससे न केवल सैन्य क्षमता बढ़ेगी बल्कि देश में विशाल रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित होगा।

इसी दिशा में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है जहां अब तक 35000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हो चुका है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत को वैश्विक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाना है और हजारों उच्च कौशल रोजगार पैदा करना है।

चौथी रणनीतिक प्राथमिकता है नई पीढ़ी के युद्ध क्षेत्रों में प्रवेश। पारंपरिक युद्ध अब अकेला निर्णायक तत्व नहीं रह गया है। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धि आधारित युद्ध प्रणाली, डाटा युद्ध और साइबर युद्ध भविष्य की लड़ाइयों का आधार बनते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने ड्रोन बल, सैन्य जियो स्पेशल एजेंसी, डाटा फोर्स और संज्ञानात्मक युद्ध इकाइयों की स्थापना की दीर्घकालिक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक भारत पूरी तरह तकनीकी रूप से उन्नत सैन्य शक्ति बन सके।

पांचवीं प्राथमिकता है रक्षा निर्यात का आक्रामक विस्तार। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हथियार आयातक देश की छवि से बाहर निकलकर रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत से लगभग 3800 करोड़ रुपये की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है। यह सौदा केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सामरिक उपस्थिति मजबूत होती है। छठी रणनीतिक दिशा है भविष्य के युद्ध खतरों के लिए तैयारी। भारत की नई रक्षा दृष्टि में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हमलों से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा ढांचे का निर्माण भी शामिल है। रक्षा बल विजन 2047 दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य के युद्ध बहुआयामी होंगे और उनके लिए तेज प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

इन सभी पहलों का व्यापक लक्ष्य है भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित और सैन्य दृष्टि से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। देखा जाये तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत रक्षा विजन 2047 राष्ट्रीय शक्ति के समग्र विस्तार का खाका है जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार को एक साथ जोड़ा गया है।

कुल मिलाकर देखें तो वर्ष 2026 में मोदी सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं बेहद स्पष्ट और आक्रामक हैं। विशाल रक्षा बजट, तेज सैन्य आधुनिकीकरण, स्वदेशी हथियार निर्माण, नई युद्ध तकनीकों में निवेश, रक्षा निर्यात का विस्तार और भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी, ये सभी कदम मिलकर भारत को एक उभरती वैश्विक सैन्य शक्ति में बदलने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। यदि यह रणनीति इसी गति से लागू होती रही तो आने वाले दशक में भारत केवल दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र नहीं रहेगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की शक्ति संतुलन राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा।

# राम मंदिर से काशी कॉरिडोर तक यूपी में सांस्कृतिक पुर्नजागरण

इंद्रेश शर्मा

वर्ष 2017 में विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी भाजपा गठबंधन की सरकार ने नौ वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन नौ वर्षों में सरकार ने कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा विकास के अनेक प्रतिमान गढ़े हैं। अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए सरकार ने, "नवनिर्माण के नौ वर्ष" नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है। वर्ष 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश अराजकता के जाल में फंसा हुआ था। छोटी -छोटी बातों पर फसाद हो जाते थे। कानून और व्यवस्था की बुरी स्थिति के कारण निवेशक यहां आने से डरते थे। मुस्लिम तुष्टिकरण चरम पर था। लोग उल्टा प्रदेश कहकर प्रदेश का उपहास करते थे। 2017 में योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद से इस स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि

अब प्रदेश की पहचान का संकट समाप्त हो चुका है, सुरक्षा निवेश व विकास प्रदेश की नई पहचान बन चुके हैं। प्रदेश में सभी पर्व शांति, सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं।

कहीं कोई तनाव, कर्फ्यू व दंगा नही है। ऐसे माफियाओं का अंत हुआ है जिनके सामने सपा, बसपा व कांग्रेस की पुरानी सरकारें नतमस्तक हो जाया करती थीं। शासन व्यवस्था में सुधार व मजबूत कानून व्यवस्था के कारण आज प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद अयोध्या में दिव्य व भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या को अपना एयरपोर्ट, आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशन, मेडिकल कालेज मिला, सम्पूर्ण अयोध्या नगरी का नवीनतम और पुरातन संस्कृति के सामंजस्य व समन्वय के साथ व्यापक स्तर पर विकास हो रहा है। इसी प्रकार काशी का विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण से काशी का स्वरूप भी निखरकर सामने आ रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाकर इतिहास रच दिया। इसी प्रकार मां विन्ध्यवासिनी कॉरिडोर के निर्माण से मां विन्ध्यवासिनी जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक विशेष अनुभूति व आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अन्य पर्यटन गतिविधियों का विकास होने के कारण इस क्षेत्र में युवाओ के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रदेश की आस्था, संस्कृति व परंपराओं को सम्मान देते हुए उन्हें नई पहचान दिलाने का प्रयास लगातार जारी है।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 96 लाख एमएमएमई इकाइयां संचालित की जा रही हैं। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। एक जिला-एक उत्पाद योजना, एक जिला एक व्यंजन योजना के साथ ही प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है। विगत नौ वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, किसानों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबों के उत्थान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए हैं। अनेकानेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दलितों, वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंच रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सेवा क्षेत्रों में सुधार करते हुए सुशासन की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रदेश में हिंदू समाज के मतांतरण को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाया गया और साथ ही लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रदेश सरकार कनून लेकर आई।

बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया। महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम सरकार द्वारा समय-समय पर उठाए जाते रहे हैं। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति अभियान प्रदेशभर में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना से बेटियां सशक्त हो रही हैं। प्रदेश की पीएसी को जीवन्त करते हुए प्रदेश में पहली बार पीएसी मे महिलाओं के लिए तीन नई बटालियन की शुरूआत की गई। गरीब बेटियों के लिए विवाह के समय दी जाने वाली सरकारी सहायता भी बढ़ा दी गई है। मेधावी बेटियों के लिए स्कूटी योजना आई है। प्रदेश का विकास परिवर्तनकारी है आज प्रदेश में सात एक्सप्रेस वे संचालित हैं, 15 का विकास कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 16 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं और 8 निमाणार्धीन हैं। बहु प्रतीक्षित जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आगामी 28 मार्च, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सात प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा चल रही है।

नई सड़क परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए पहचान बन चुकी हैं। वाराणसी से प्रयागराज और बलिया से अयोध्या तक वाटर-वे की सुविया बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश तीव्र गति से विकसित प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। खाद्यान्न, गन्ना, आम एवं दुग्ध उत्पादन सहित अनेक क्षेत्रों में यूपी देश के पहले पायदान पर पहुंच चुका है। प्रदेश के किसानों को पूरी ईमानदारी से, समय पर भुगतान तो हो रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व्यापक योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों तक केंद्र व राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। निवेश लाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी ने जापान और सिंगापुर का सफल दौरा किया जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी का सफल दौरा किया। नौकरियां मिल चुकी हैं। युवाओं के लिए सरकार ने कई कदम उठाए तथा ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं जिनके अंतर्गत अब प्रदेश सरकार युवाओं को एआई जैसे नये क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित करने जा रही है। सरकार ने युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग चलाई जिससे हजारों छात्र सफल होकर नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली सरकार में हिंदुओं के आस्था केंद्रों का सम्मान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर क्षण जनसमस्याओं के समाधान के प्रति कार्यरत रहते हैं। उन्होंने जनता दरबार के साथ साथ, जनता से सीधे जुड़े रहने के लिए योगी की पाती लिखनी आरम्भ की है। मुख्यंमत्री ने "नवनिर्माण के नौ वर्ष" पुस्तक विमोचन के अवसर पर सनतान का संदेश दिया और भविष्य की दृष्टि भी स्पष्ट की।

# धर्म, जाति और धर्मांतरण: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

**भारत में अनुसूचित जाति की व्यवस्था का निर्माण किसी धर्म विशेष को लाभ देने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उन सामाजिक वर्गों को संरक्षण और अवसर देने के लिए किया गया था, जो सदियों से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते रहे थे।**

अनादि शुक्ल

धर्म, जाति और धर्मांतरण का प्रश्न भारत के सामाजिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील और जटिल विषय है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेता है तो वह अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा और उससे जुड़े लाभों का अधिकारी नहीं रहेगा, केवल एक सामान्य कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय की अवधारणा और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दिया गया एक दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय को भारतीय न्याय व्यवस्था की परिपक्वता, संतुलन और दूरदर्शिता का प्रतीक कहा जा सकता है।

भारत में अनुसूचित जाति की व्यवस्था का निर्माण किसी धर्म विशेष को लाभ देने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उन सामाजिक वर्गों को संरक्षण और अवसर देने के लिए किया गया था, जो सदियों से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते रहे थे। संविधान निमार्ताओं ने यह माना था कि समाज में जो ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक असमानता रही है, उसे दूर किए बिना वास्तविक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। इसी कारण आरक्षण और विशेष कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था मूलतः सामाजिक भेदभाव पर आधारित थी, आर्थिक आधार पर नहीं। इसलिए अनुसूचित जाति का प्रश्न धर्म से अधिक सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ था। जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ऐसे धर्म को स्वीकार करता है, जहां जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जाती, तो फिर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या उसे उसी आधार पर अनुसूचित जाति के लाभ मिलते रहने चाहिए। इसी प्रश्न को लेकर वर्षों से देश में बहस चलती रही है। कई मामलों में यह देखा गया कि व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वह दूसरे धर्म की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भी हो गया, लेकिन वह अनुसूचित जाति के आरक्षण, छात्रवृत्ति, नौकरी में आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट जैसे कानूनों का लाभ लेना चाहता था। इससे एक प्रकार की कानूनी और सामाजिक विसंगति उत्पन्न हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसी विसंगति को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और यह स्पष्ट करता है कि संविधान द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग उसी सामाजिक संदर्भ में किया जा सकता है, जिसके लिए वे बनाई गई थीं।

धर्मांतरण का प्रश्न भारत में केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं रहा है, बल्कि कई बार यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनसंख्या

संतुलन से भी जुड़ जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर गरीब, वंचित और अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों में धर्मांतरण की घटनाएँ समय-समय पर सामने आती रही हैं। कई बार धर्मांतरण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहायता के माध्यम से हुआ, तो कई बार लालच, प्रलोभन, दबाव या सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी धर्म परिवर्तन के आरोप लगे। इसी कारण कई राज्यों ने धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए, ताकि बल, प्रलोभन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोका जा सके, लेकिन इन कानूनों का प्रभाव उतना व्यापक नहीं हो पाया जितनी अपेक्षा थी।

जब किसी विशेष सामाजिक वर्ग का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव केवल धर्म पर ही नहीं पड़ता, बल्कि जातीय संरचना, सामाजिक संतुलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता है। धीरे-धीरे यह स्थिति सामाजिक और धार्मिक संतुलन को प्रभावित करने लगती है।

भारत जैसे बहुधर्मी और बहुजातीय देश में सामाजिक और धार्मिक संतुलन का बने रहना राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि समाज लगातार जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बदलता और विभाजित होता रहेगा, तो इसका प्रभाव सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता पर पड़ना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से धर्मांतरण का प्रश्न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय संतुलन का भी प्रश्न बन जाता है।

आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य भी यही था कि जो लोग सामाजिक रूप से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में अवसर मिल सके। लेकिन यदि धर्म परिवर्तन के बाद भी लोग आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे, तो इससे आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा और वास्तविक जरूरतमंद लोगों के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे समाज में असंतोष और असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आरक्षण व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि संविधान की सुविधाएँ अधिकार हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता है। यहां अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां होते हुए भी देश एक है। लेकिन यदि धर्म, जाति और जनसंख्या संतुलन को लेकर लगातार राजनीतिक और सामाजिक प्रयोग होते रहेंगे, तो इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है। धर्मांतरण यदि पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था और विचार की स्वतंत्रता के आधार पर हो तो वह व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन यदि वह लालच, भय, दबाव, सामाजिक अलगाव या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो, तो वह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय संतुलन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया बन जाता है। इसलिए इस विषय पर संतुलित, संवेदनशील और राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। यह निर्णय केवल यह नहीं कहता कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह निर्णय संविधान की मूल भावना को भी स्पष्ट करता है कि सामाजिक न्याय का आधार सामाजिक वास्तविकता है, न कि केवल कानूनी तकनीक। यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि संविधान द्वारा दी गई सुविधाओं का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है, न कि कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग होने देना।

आज भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था केवल तकनीकी व्याख्याओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सामाजिक वास्तविकता, राष्ट्रीय हित और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर निर्णय दिए जा रहे हैं। इस दृष्टि से यह निर्णय नए भारत की कानूनी सोच और संवैधानिक दृष्टि का प्रतीक भी कहा जा सकता है। यह निर्णय यह संदेश देता है कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता दोनों साथ-साथ चल सकते हैं और संविधान दोनों की रक्षा करने में सक्षम है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि धर्म, जाति, आरक्षण और धर्मांतरण का प्रश्न भारत में लंबे समय से विवाद और बहस का विषय रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस जटिल विषय को स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल आरक्षण व्यवस्था अधिक स्पष्ट और न्यायसंगत बनेगी, बल्कि धर्मांतरण और कानूनी लाभ के बीच जो विसंगतियाँ थीं, वे भी काफी हद तक समाप्त होंगी। यह निर्णय सामाजिक संतुलन, कानूनी स्पष्टता और राष्ट्रीय एकता-तीनों को मजबूत करने वाला निर्णय है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि यह निर्णय केवल एक न्यायालय का फैसला नहीं, बल्कि नए भारत, सशक्त भारत और संगठित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए।

# BRICS के विस्तार ने बढ़ाई भारत की ताकत

**पहले ब्रिक्स सिर्फ पांच देशों का समूह था, जिसकी कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगभग 31 प्रतिशत के आसपास थी। लेकिन विस्तार के बाद इसमें नए सदस्य जुड़ने से यह आंकड़ा लगभग 37 से 40 प्रतिशत तक पहुँच गया है।**

ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक शक्ति संतुलन की बिसात पर ऐसा दांव चला है, जिसने पश्चिमी प्रभुत्व को खुली चुनौती दे दी है। भारत के लिए यह उभरती विश्व व्यवस्था में अपनी निर्णायक भूमिका दर्ज कराने का सुनहरा अवसर बन चुका है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब ब्रिक्स का विस्तार भारत की सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला कारक बनकर सामने आया है।

पहले ब्रिक्स पांच देशों का समूह था, जिसकी कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी

कपिल शर्मा

लगभग 31 प्रतिशत के आसपास थी। लेकिन विस्तार के बाद इसमें नए सदस्य जुड़ने से यह आंकड़ा लगभग 37 से 40 प्रतिशत तक पहुँच गया है। जनसंख्या के लिहाज से भी यह समूह अब दुनिया की लगभग 45 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अब ऐसे मंच का प्रमुख स्तंभ है जो आर्थिक, जनसंख्या और संसाधनों के मामले में पश्चिमी देशों को बराबरी की टक्कर दे सकता है।

भारत के लिए सबसे बड़ा सामरिक लाभ यह है कि ब्रिक्स के जरिए वह डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के विकल्प को मजबूत करने में भूमिका निभा सकता है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाएं पहले ही पश्चिमी वित्तीय संस्थानों के एकाधिकार को चुनौती दे रही हैं। यदि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा मिलता है, तो भारत को विदेशी मुद्रा दबाव से राहत मिलेगी और उसकी आर्थिक संप्रभुता

मजबूत होगी। सामरिक स्तर पर भी यह विस्तार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई नए सदस्य देशों के जुड़ने से भारत की पहुंच ऊर्जा संसाधनों, समुद्री मार्गों और रणनीतिक क्षेत्रों तक बढ़ेगी। यह वही क्षेत्र हैं जहां अब तक चीन अपनी पकड़ मजबूत करता रहा है। ब्रिक्स के भीतर सक्रिय भूमिका निभाकर भारत इस प्रभाव को संतुलित कर सकता है और खुद को एक भरोसेमंद शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है।

अब सवाल उठता है कि इस वर्ष भारत में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या मौजूदा वैश्विक तनावों के बीच संभव हो पाएगा? देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, रूस और पश्चिम के बीच टकराव, और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक माहौल को बेहद जटिल बना दिया है। लेकिन इतिहास बताता है कि संकट के दौर में ही ऐसे मंचों की अहमियत बढ़ जाती है। संभावना यही है कि सम्मेलन आयोजित होगा, भले ही कुछ नेताओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष की बजाय ऑनलाइन माध्यम से हो।

वैसे असल चुनौती यह नहीं है कि सम्मेलन होगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या सदस्य देश एक साझा एजेंडा पर सहमत हो पाएंगे? उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स के भीतर भी मतभेद हैं। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद, रूस और पश्चिम के बीच युद्ध एवं पश्चिम एशिया के देशों के संघर्ष इस मंच की एकता की परीक्षा ले रहे हैं। फिर भी, आर्थिक हित और वैश्विक संतुलन की जरूरत इन देशों को एक साथ बैठने के लिए मजबूर करती है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट ने ब्रिक्स की प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। जहां पश्चिमी देश अक्सर पक्षपातपूर्ण रुख अपनाते दिखते हैं, वहीं ब्रिक्स एक संतुलित और बहुपक्षीय समाधान की बात करता है। भारत, जो खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वह इस मंच के जरिए शांति पहल को निश्चित रूप से आगे बढ़ा सकता है।

वर्तमान वैश्विक संकटों के संदर्भ में भी देखें तो समाधान की दिशा में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है। भारत पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि वह संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के आधार पर समाधान चाहता है। भारत यदि मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो वह न केवल अपनी वैश्विक छवि को मजबूत करेगा बल्कि ब्रिक्स को भी एक प्रभावी संकट समाधान मंच के रूप में स्थापित कर सकता है।

आंकड़ों की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ते हुए दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और अगले कुछ वर्षों में इसके तीसरे स्थान तक पहुंचने का अनुमान है।

ऐसे में ब्रिक्स के भीतर भारत की भूमिका केवल एक सदस्य की नहीं बल्कि एक दिशा तय करने वाली शक्ति की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत की पहलें ब्रिक्स देशों के लिए मॉडल बन सकती हैं।

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि ब्रिक्स का विस्तार भारत के लिए एक रणनीतिक वरदान है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यदि भारत इन चुनौतियों को संतुलित करते हुए इस मंच का प्रभावी उपयोग करता है, तो वह न केवल अपनी वैश्विक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। यह समय भारत के लिए सिर्फ भागीदारी का नहीं, बल्कि नेतृत्व का है।

# खाकी का 'संकल्प' और अपराधियों का 'काल'

# एडिशनल सीपी केशव कुमार चौधरी

## दरभंगा की गलियों से गाजियाबाद के 'कमान' तक: आईपीएस केशव कुमार चौधरी—साहस और सुचिता का संगम

संजय मित्तल

कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। बिहार के दरभंगा की मिट्टी से उपजा एक ऐसा ही 'हौसला' आज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की सुरक्षा दीवार को मजबूती दे रहा है। आईपीएस केशव कुमार चौधरी (2009 बैच) केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद आसमान छूने का जज्बा रखते हैं।

### यूपीएससी का सफर: दूसरे प्रयास में गाड़ा सफलता का झंडा

9 जनवरी 1981 को जन्मे केशव कुमार चौधरी का बचपन कलेक्ट्रेट की फाइलों और अनुशासन के बीच बीता। पिता कलेक्ट्रेट में कार्यरत थे, इसलिए प्रशासनिक गलियारों की सेवा और सम्मान को उन्होंने करीब से देखा था।

दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के बाद, उन्होंने यूपीएससी को अपना लक्ष्य बनाया। पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद जब अंतिम चयन नहीं हुआ, तो उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कमियों को ताकत बनाया। परिणाम स्वरूप, वर्ष 2009 में 137वीं रैंक हासिल कर उन्होंने आईपीएस की वर्दी पहनी।

## डकैतों के लिए 'खौफ' और जनता के लिए 'रक्षक'

केशव कुमार चौधरी की कार्यशैली की चर्चा उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में रही है। विशेषकर चित्रकूट में तैनाती के दौरान उन्होंने बीहड़ों में जो पराक्रम दिखाया, उसे आज भी याद किया जाता है। डकैतों के खिलाफ चलाए गए उनके विशेष अभियान ने कई कुख्यात गिरोहों का सफाया कर दिया और सालों से डरे हुए ग्रामीणों के मन में खाकी के प्रति विश्वास जगाया। झांसी में डीआईजी और बहराइच में एसएसपी के रूप में उनके 'एक्शन' ने अपराधियों की कमर तोड़ दी थी।

## गाजियाबाद में 'स्मार्ट और सख्त' पुलिसिंग का चेहरा

गाजियाबाद में एडिशनल पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद केशव कुमार चौधरी ने तकनीकी और फील्ड पुलिसिंग के बीच एक शानदार संतुलन बनाया है, अपराध पर प्रहार करने के लिए उन्होंने गाजियाबाद में स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए 'इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग' पर जोर दिया । आगरा और झांसी का अनुभव लेकर जब वे गाजियाबाद आए, तो उन्होंने विभाग के भीतर

अनुशासन और जनता के प्रति जवाबदेही को प्राथमिकता दी, केशव कुमार चौधरी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 2021 में डीजीपी सिल्वर डिस्क और 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर डीजीपी गोल्ड डिस्क से सम्मानित किया गया, जो उनकी अटूट कर्तव्यनिष्ठा का प्रमाण है।

## जीवन का मूलमंत्रः सादगी और अनुशासन

केशव कुमार चौधरी के जीवन से जुड़ी एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है उनकी 'जड़ों से जुड़ाव'। केशव कुमार चौधरी आज भी अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता के अनुशासन और दरभंगा की उस साधारण परवरिश को देते हैं। वे अक्सर युवा अभ्यर्थियों से कहते हैं, 'सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही रणनीति और ईमानदारी से मिलती है'। ड्यूटी के दौरान वे किसी भी मामले की तह तक जाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह आधी रात को बीहड़ में डकैतों का पीछा करना हो या शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना।

## गाजियाबाद पुलिसिंग में बड़ा बदलाव

एडिशनल सीपी के तौर पर उन्होंने गाजियाबाद में पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाना और पुलिस रिस्पांस टाइम को कम करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। उनके आने के बाद गाजियाबाद पुलिसिंग में एक 'प्रोफेशनल' बदलाव महसूस किया गया है। अनुभव का विशाल समंदर और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता– यही केशव कुमार चौधरी की पहचान है। गाजियाबाद कमिश्नरेट को उनके जैसे अनुभवी और जांबाज अधिकारी का साथ मिलना, शहर की सुरक्षा के लिए एक सुखद गारंटी है।

# सपा के दलित समर्थकों में भाजपा लगाएगी सेंध

राहुल अग्रवाल

देश में आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों ने अपनी अपनी चुनावी राजनीति बनानी शुरु कर दी है। लेकिन इस मुहिम में सबसे ज्यादा सक्रिय सत्तारुढ दल भाजपा व मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी के ही चुनावी रणनीतिकार नजर आ रहे हैं। भाजपा का जहां जीत की हैट्रिक लगाने का लक्ष्य है, वहीं सपा सत्ता वापसी का सपना देख रही है। इसी को लेकर दोनों दल एक दूसरे की मात देने की रणनीति बनाने में माथापच्ची करने में लग गये हैं। हालांकि बसपा मुखिया मायावती ने भी लखनऊ में पार्टी नेताओं की बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार की है और वह भी आगामी चुनाव में पूरी मुस्तैदी से अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी की गतिविधियां व सक्रियता कम ही नजर आ रही है। बसपा के लिए यह चुनाव करो या मरो वाला है, क्योंकि बसपा का प्रदेश में एक मात्र विधायक है, जबकि लोकसभा व राज्यसभा में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो का यही प्रयास है कि किसी भी तरह के उनकी पार्टी का आगामी विधानसभा में संतोषजनक प्रदर्शन रहे ताकि पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाने वालों का मुंह स्वतः ही बंद हो जाए।

उधर एनडीए के घटक दल व सरकार में शामिल होने से राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी, अपना दल आदि दल फिलहाल अपनी कोई अलग रणनीति नही बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने ही नेताओं की आपसी गुटबाजी व बड़बोले नेताओं की बयानबाजी पर ही अंकुश नहीं लगा पा रही है। इतना ही नहीं तमाम कांग्रेसी नेता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने से भी कांग्रेस की स्थिति को कमजोर आंका जाने लगा है। इसलिए कांग्रेस प्रदेश में अभी तो विधानसभा चुनाव को लेकर अपने स्तर पर कोई रणनीति बनाती नजर नहीं आ रही है।

विधानसभा चुनाव-2027 में उप्र में सीधा मुकाबला भाजपा व सपा के बीच ही होना है। लेकिन भाजपा के लिए इस समय समाजवादी पार्टी के पीडीए को तोड़ ढूंढना बड़ी चुनौती है। हालांकि फौरी तौर पर भाजपा के रणनीतिकारों ने सपा के पीडीए को कमजोर करने का फार्मूला तैयार कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के रणनीतिकार सपा की पीडीए फार्मूले को कमजोर करना चाहती है।

भाजपा इसके लिए वह दलितों का भाजपा के प्रति रुझान करने के लिए जल्द ही प्रदेश भर में दलित महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने जा रही है। इन सम्मेलनों के माध्यम से दलितों को भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जिन महापुरूषों के नाम कार्यक्रम होने प्रस्तावित हैं उनमें डॉ. भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उदा देवी, झलकारी बाई, वीरा पासी, लखन पासी, रमाबाई अंबेडकर के नाम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा सपा से दलितों का मोह भंग करना चाहती है।

भाजपा को सबसे बड़ा डर यह है कि यदि लोकसभा चुनाव-2022 की तरह उत्तर प्रदेश में सपा का पीडीए फार्मूला कामयाब हो जाता है, तो उसके लिए विधान सभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरुर हो जाएगा। इसलिए पहले से भाजपा की रणनीति सपा के पीडीए फार्मूले को कमजोर करके सपा के सत्ता वापसी के सपने के चकनाचूर करना है।

उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव को उम्मीद है कि केवल पीडीए फार्मूले पर काम करके ही सत्ता में वापसी हो सकती है। इसलिए वे इसलिए हर संभव हथकंडे अपनाने का मन बना चुके हैं। तमाम कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं को सपा में शामिल करके वह प्रदेश की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। इसी सकारात्मक संदेश के माध्यम से वह अपनी पार्टी का कुनवा बढ़ाने में लगे हैं। इसके लिए वह अपने सहयोगी दल कांग्रेस को साथ न लेकर स्वयं के बल पर अपनी चुनावी रणनीतियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति में जल्द ही कई तरह के परिदृश्य देखने को मिल सकते हैं। उप्र में संभावित राजनीतिक स्थितियों को लेकर सभी पार्टी के रणनीतिकार पैनी नजर रखे हुए हैं।

# दूरदृष्टि और विकास का संतुलन, आम बजट में भविष्य की झलक: एस.एन. सिंह

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एस. एन. सिंह ने कहा कि हाल ही में प्रस्तुत आम बजट केवल वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह भारत के आर्थिक और सामाजिक भविष्य की दिशा को स्पष्ट करने वाला नीतिगत दस्तावेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से यह संकेत दिया है कि देश की आर्थिक नीति तात्कालिक लाभ से आगे बढ़कर दीर्घकालिक, टिकाऊ और समावेशी विकास पर केंद्रित है।

बजट की मूल भावना निवेश-आधारित विकास को गति देने की है। बुनियादी ढांचे, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल कनेक्टिविटी पर सरकार का निरंतर जोर इस बात को रेखांकित करता है कि आर्थिक वृद्धि के लिए मजबूत आधारभूत संरचना को सरकार प्राथमिकता मानती है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को विकास का इंजन बनाकर निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की रणनीति प्रधानमंत्री मोदी की उस दूरदर्शिता को दशार्ती है, जिसमें सरकार उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक गति प्रदान करती है।

निर्माण और उत्पादन क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रावधान 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच को आगे बढ़ाते हैं। उन्नत तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, हरित ऊर्जा और नवाचार आधारित उद्योगों को समर्थन देकर सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन और मूल्य-श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनना चाहता है। यह नीति न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है, बल्कि निर्यात क्षमता को भी मजबूत करती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए बजट में किए गए उपाय विशेष उल्लेख के योग्य हैं। आसान ऋण उपलब्धता, संस्थागत सहयोग और व्यावसायिक मार्गदर्शन जैसे कदम छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के

## निर्माण और उत्पादन क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रावधान 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच को आगे बढ़ाते हैं।

अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी इस बजट में स्पष्ट दिखाई देती है। कृषि अवसंरचना, ग्रामीण कनेक्टिविटी और आय-वर्धन से जुड़ी पहलों के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि विकास की धारा शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों तक समान रूप से पहुँचे। यह समावेशी दृष्टिकोण सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्रों—विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास—में निवेश यह दर्शाता है कि सरकार आर्थिक प्रगति को मानवीय विकास से अलग नहीं देखती। स्वस्थ, शिक्षित और कुशल नागरिक ही किसी भी राष्ट्र की वास्तविक पूंजी होते हैं।

इस दिशा में बजट के प्रावधान दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को साधने वाले हैं। कुल मिलाकर, यह आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की नीति-स्पष्टता, वित्तीय अनुशासन और राष्ट्र-निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ भविष्य के अवसरों के लिए भारत को तैयार करने का प्रयास करता है। कहा जा सकता है कि यह बजट विकास, विश्वास और दूरदृष्टि का संतुलित दस्तावेज है, जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

# इंडो पैसेफिक में भारत कैसे बनता जा रहा है सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति?

**हम आपको बता दें कि इंडो पैसेफिक में भारत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार की जीवन रेखा है। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। भारत के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा समुद्री मार्गों से संचालित होता है।**

21 वीं सदी की वैश्विक राजनीति का केंद्र तेजी से इंडो पैसेफिक क्षेत्र बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह वही भू क्षेत्र है जहां विश्व की लगभग 65 प्रतिशत आबादी रहती है, वैश्विक सकल उत्पादन का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा उत्पन्न होता है और दुनिया के करीब आधे समुद्री व्यापार का संचालन होता है। ऐसे रणनीतिक और आर्थिक महत्व वाले क्षेत्र में भारत की भूमिका पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है। यह केवल संयोग नहीं बल्कि भारतीय विदेश नीति की दूरदर्शिता, संतुलन और आक्रामक कूटनीति का परिणाम है।

हम आपको बता दें कि इंडो पैसेफिक में भारत

हरेन्द्र शर्मा

की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार की जीवन रेखा है। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। भारत के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा समुद्री मार्गों से संचालित होता है। इस कारण हिंद महासागर की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की स्थिरता भारत के लिए केवल रणनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है। भारत ने इसी दृष्टि से अपनी विदेश नीति को समुद्री शक्ति, समुद्री संपर्क और समुद्री सहयोग से जोड़ा है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी उसे इस क्षेत्र में स्वाभाविक शक्ति बनाती है। भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट है। यह वही मार्ग है जिससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच भारी मात्रा में व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीपों और समुद्री मार्गों की निगरानी करने की क्षमता भारत को इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका प्रदान करती है।

वैसे इंडो पैसेफिक में भारत की भूमिका के बढ़ने का एक बड़ा कारण चीन की बढ़ती आक्रामकता भी है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया है। बंदरगाह निर्माण, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और ऋण आधारित अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से चीन ने इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया है। इस परिस्थिति में अनेक देशों ने भारत को संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में देखा है। यही कारण है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने भारत के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है। क्वॉड सुरक्षा संवाद जैसे मंचों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग विकसित हुआ है। इससे भारत की सामरिक और कूटनीतिक क्षमता दोनों में वृद्धि हुई है।

भारतीय विदेश नीति की सफलता इस बात में भी दिखाई देती है कि भारत ने इंडो पैसेफिक को केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं देखा बल्कि उसे आर्थिक और विकासात्मक सहयोग के मंच के रूप में भी विकसित किया। भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार, निवेश और संपर्क के नए मार्ग विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, भारत ने क्षेत्रीय संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। हिंद महासागर रिम संघ, बिमस्टेक और अन्य बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से भारत समुद्री सहयोग, व्यापार और संपर्क को बढ़ावा दे रहा है। इन मंचों के माध्यम से भारत क्षेत्रीय विकास और सामूहिक सुरक्षा की नीति को आगे बढ़ा रहा है।

साथ ही समुद्री अवसंरचना के क्षेत्र में भी भारत ने बड़े स्तर पर निवेश शुरू किया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत देश के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, समुद्री परिवहन का विस्तार और तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग एक सौ बीस अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई गई है। इसके अलावा भारत ने दीर्घकालिक दृष्टि से समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए विशाल निवेश योजनाएं तैयार की हैं जिनका उद्देश्य भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना है। इसके अलावा, भारत की नौसैनिक क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी, मानवीय सहायता, आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा अभियानों में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अनेक अवसरों पर भारत ने संकट के समय पड़ोसी देशों की सहायता कर यह साबित किया है कि वह जिम्मेदार नेतृत्व भी प्रदान कर सकता है देखा जाये तो इंडो पैसेफिक के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित और समावेशी कूटनीति है। भारत किसी सैन्य गुट की राजनीति को बढ़ावा देने की बजाय मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसेफिक की अवधारणा का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन केंद्रीय तत्व है। आज स्थिति यह है कि इंडो पैसेफिक की किसी भी रणनीतिक चर्चा में भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं रहा है। वैश्विक शक्तियां भारत को इस क्षेत्र की स्थिरता और संतुलन का अनिवार्य स्तंभ मानने लगी हैं। यह परिवर्तन भारत की विदेश नीति की निर्णायक सफलता को दशार्ता है।

बहरहाल, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इंडो पैसेफिक में भारत की बढ़ती भूमिका एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत है। समुद्री शक्ति, आर्थिक क्षमता, सक्रिय कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों के संयोजन ने भारत को इस क्षेत्र की केंद्रीय शक्ति बना दिया है।

आने वाले वर्षों में जब वैश्विक राजनीति का केंद्र और अधिक तेजी से इंडो पैसेफिक की ओर स्थानांतरित होगा, तब इस कहानी के केंद्र में भारत की भूमिका और भी निर्णायक होती दिखाई देगी।

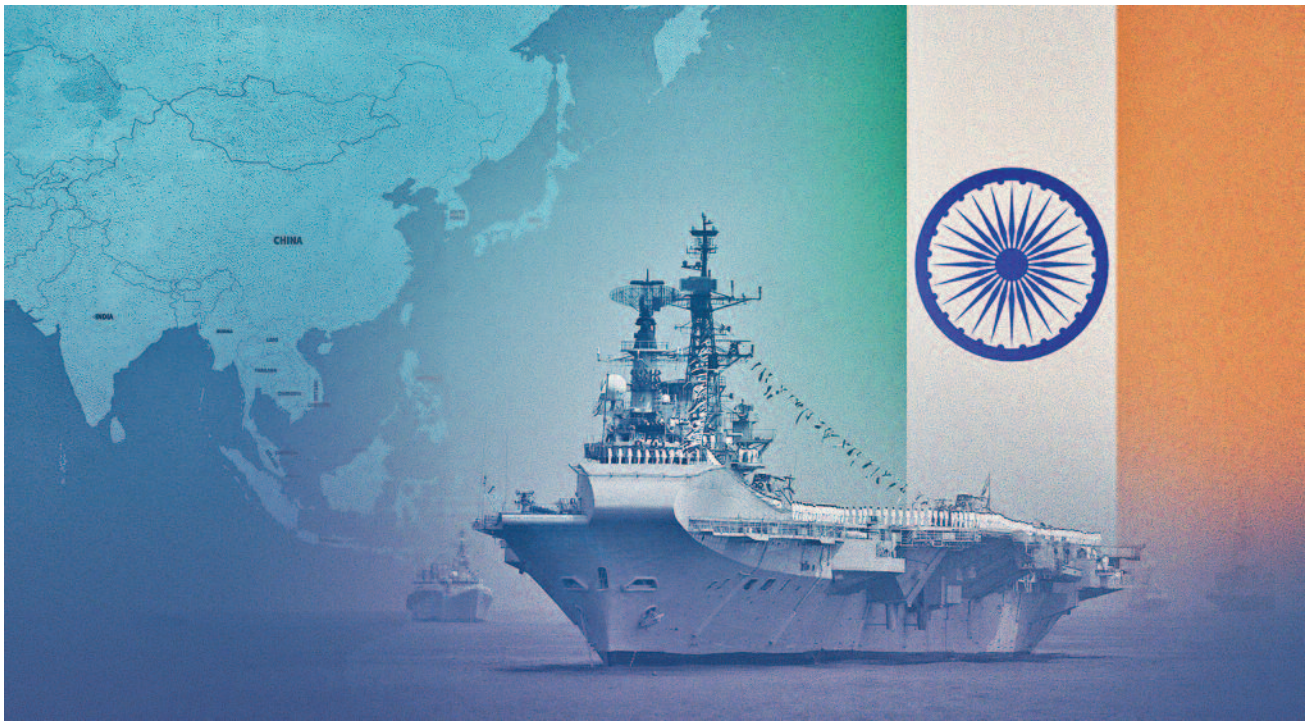

# ममता को झटका देने की तैयारी

संजय बैंसला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम चीफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के चर्चित मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से बहुस्तरीय और जटिल रही है, जहां जाति, धर्म, क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक रणनीति एक साथ मिलकर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। एआईएमआईएम और जेयूपी के साथ गठबंधन इसी जटिलता में एक नये आयाम जोड़ना वाला है। यह नया गठबंधन केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की पुनर्संरचना कर परिणामों को प्रभावित करेगा। खासकर उस राज्य में, जहां करीब 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी चुनावी परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डालती है, वहां इस नए गठबंधन के दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों के मुताबिक राज्य की सौ से अधिक सीटों पर इस गठबंधन का टीएमसी को नुकसान और भाजपा को फायदा मिलेगा। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बिखरने का खामियाजा ममता बनर्जी के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ेगा।

## मुस्लिम वोट बैंक: पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर निर्णायक

पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30 प्रतिशत मानी जाती है, जो राज्य की करीब 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर प्रभाव डालती है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और कुछ हद तक नदिया जैसे जिलों में यह प्रभाव और भी स्पष्ट दिखाई देता है। अब तक यह वोट बैंक काफी हद तक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ रहा है, जिसने खुद को अल्पसंख्यकों के भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित किया। लेकिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हुमायूं कबीर को इसी बात पर पार्टी से निकालकर ममता ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने वोट बैंक को नाराज कर लिया है। हुमायूं कबीर अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनवा रहे हैं, जिसका नाम भी उन्होंने बाबरी मस्जिद ही रखा है। हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन ममता बनर्जी के इसी स्थिर समीकरण को चुनौती देता नजर आ रहा है।

## ओवैसी की एंट्री: रणनीतिक सेंधमारी खिलाएगी नया गुल

ओवैसी की राजनीति अक्सर उन राज्यों में प्रभाव डालती रही है, जहां मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा किसी एक दल के साथ जुड़ा होता है।

बंगाल में उनकी एंट्री भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। एआईएमआईएम की मुस्लिम वोटों में पकड़ मानी जाती है। ऐसे में हुमायूं कबीर से जुड़कर उन्होंने मुस्लिमों की धार्मिक भावना को भी हवा दी है। ओवैसी-कबीर की जोड़ी के चलते मुस्लिम वोटों के बिखराव से कई सीटों पर परिणाम बदल सकता है। अगर मुस्लिम वोटों का छोटा हिस्सा भी टीएमसी से हटकर इस नए गठबंधन की ओर जाता है, तो यह सीधे तौर पर तृणमूल के नुकसान और विपक्ष, खासकर भाजपा, के लिए लाभ का कारण बन सकता है।

## हुमायूं कबीर फैक्टर: स्थानीय प्रभाव और असंतोष की राजनीति

हुमायूं कबीर का राजनीतिक महत्व उनके स्थानीय प्रभाव और टीएमसी से अलगाव के कारण बढ़ जाता है। टीएमसी से निष्कासन के बाद उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी बनाकर खुद को एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका यह दावा कि ममता की टीएमसी में मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, एक ऐसी बहस को जन्म देता है जो तृणमूल के पारंपरिक वोट बैंक में असंतोष पैदा कर सकती है। उनके द्वारा बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारना इस बात का संकेत है कि वे केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं, बल्कि वास्तविक चुनावी चुनौती पेश करना चाहते हैं।

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण जैसे मुद्दों को उठाकर हुमायूं कबीर ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को सीधे छूने की कोशिश की है। यह मुद्दा भावनात्मक रूप से कुछ वर्गों को प्रभावित कर सकता है। यह तो तय है कि इसका सियासी चुनाव पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन यह कितना व्यापक असर डालेगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। बंगाल की राजनीति परंपरागत रूप से धार्मिक मुद्दों पर भी आधारित रही है। एक ओर जहां हिंदू समुदाय की मां दुर्गा में आस्था है, वहीं दूसरे धर्म के लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। यहां सामाजिक समीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ऐसे मुद्दे चुनावी विमर्श को प्रभावित जरूर करते हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार मुस्लिम धर्म के आधार पर नया गठबंधन आने से यदि मुस्लिम वोटों में विभाजन होता है, तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन एकजुट मुस्लिम वोटिंग ने टीएमसी को बढ़त दिलाई। अब अगर यही वोट बैंक विभाजित होता है, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उन सीटों पर बढ़त मिल सकती है जहां वह पहले मामूली अंतर से पीछे रह गई थी। इसके अलावा एंटी एन्कंबेंसी फैक्टर भी ममता बनर्जी की टीएमसी को मुश्किलों में डाल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नया गठबंधन चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से बदल पाएगा। इसका जवाब कई कारकों पर निर्भर करता है। गठबंधन की संगठनात्मक ताकत, उम्मीदवारों की स्थानीय पकड़, और मतदाताओं का वास्तविक रुझान। अभी तक के संकेत बताते हैं कि यह गठबंधन सीधे सत्ता परिवर्तन का कारण भले न बने, लेकिन कई सीटों पर 'स्पॉइलर' की भूमिका निभा सकता है। दरअसल, बड़े तौर पर विधानसभा चुनाव में भाजपा और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट भी अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब ओवैसी-कबीर के गठबंधन के भी आ जाने से मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन इस बदलाव का प्रतीक है, जो चुनावी समीकरणों को जटिल बना सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय मतदाता ही करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव टीएमसी को झटका देने वाला हो सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना ने स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाओं को आहत किया है। किसी भी धर्म, प्रतीक या आस्था से जुड़ी वस्तु पर हमला केवल एक स्थानीय घटना नहीं होती, बल्कि उसका प्रभाव व्यापक सामाजिक मनोविज्ञान पर पड़ता है। बेहद चिंताजनक पहलू यह भी है कि ममता राज का हिंदू विरोधी चेहरा पहली बार उजागर नहीं हुआ है। इससे पहले भी मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार कई बार हिंदू आस्था पर हमला कर चुकी हैं। यहां तक कि उन्हें जय श्रीराम के नारे तक पर आपत्ति रही है और अब उनके ही नेता और पूर्व मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने मयार्दा पुरुषोत्तम राम को सिर्फ उत्तर भारत का भगवान घोषित कर दिया है। एक तो पहले ही भगवान राम की मूर्ति का सिर काटने के कृत्य से हिंदू जनमानस आहत है, उस पर सिन्हा की टिप्पणी ने आग में घी का काम किया है। ऐसी घटनाएं और बयानबाजी न केवल धार्मिक संवेदनशीलता को झकझोरती हैं, बल्कि समाज में अविश्वास और तनाव की स्थिति भी पैदा करती हैं। इसलिए इस घटना को केवल एक आपराधिक कृत्य मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा।

## रामनवमी के उत्सव से पहले नंदीग्राम में श्रीराम की मूर्ति का सिर काटा

पश्चिम बंगाल में हिंदू आस्था पर हमले का एक और मामला सामने आया है। राम नवमी के लिए तैयार की जा रही भगवान राम की एक मूर्ति के सिर को 'जिहादी' काटकर ले गए। यह घटना नंदीग्राम के ब्लॉक-2 के वेटुरिया बस स्टैंड की है जहाँ प्रभु श्री राम की मूर्ति लगभग तैयार हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले ही मूर्ति का सिर काटकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, काम खत्म होने के बाद मूर्ति को वहीं बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया था। जब अगली सुबह कारीगर लौटे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का सिर गायब है। कई लोगों ने इस घटना को सनातन हिंदू आस्था पर हमला बताया है। यह घटना उस समय हुई जब रामनवमी के उत्सव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं, जिससे स्वाभाविक रूप से लोगों में आक्रोश और असंतोष बढ़ा।

# चाइना के मुकाबले इंडिया की रक्षा तैयारी कितनी मजबूत है ?

**सबसे पहले सैन्य संख्या की बात करें तो चीन के पास लगभग बीस लाख सक्रिय सैनिक हैं जबकि भारत के पास करीब चौदह से पंद्रह लाख के बीच सक्रिय सेना है। पहली नजर में यह अंतर बड़ा लगता है, लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता।**

एशिया की भू राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। एक तरफ विस्तारवादी मंशा से आगे बढ़ता चीन है और दूसरी तरफ तेजी से आत्मनिर्भर और आक्रामक रणनीति अपनाता भारत है। सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बल्कि सवाल यह है कि अगर टकराव हुआ तो कौन भारी पड़ेगा। तथ्य बताते हैं कि चीन अभी भी संसाधनों और संख्या के

अजीत शर्मा

मामले में आगे है, लेकिन भारत ने पिछले एक दशक में जो रणनीतिक बदलाव किए हैं, उन्होंने इस अंतर को तेजी से कम किया है। सबसे पहले सैन्य संख्या की बात करें तो चीन के पास लगभग बीस लाख सक्रिय सैनिक हैं जबकि भारत के पास करीब चौदह से पंद्रह लाख के बीच सक्रिय सेना है। पहली नजर में यह अंतर बड़ा लगता है, लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। भारत के पास अर्धसैनिक बलों का विशाल ढांचा है जो युद्ध की स्थिति में बड़ी ताकत बन सकता है।

हथियारों और तकनीक की बात करें तो वायु

शक्ति के मामले में तस्वीर साफ तौर पर चीन के पक्ष में झुकी हुई नजर आती है। कुल सैन्य विमान बेड़े में चीन के पास लगभग 3300 से अधिक विमान हैं, जबकि भारत के पास करीब 2229 विमान हैं। यानी संख्या के लिहाज से चीन को स्पष्ट बढ़त हासिल है। अगर केवल लड़ाकू विमानों की बात करें तो यह अंतर और भी चौड़ा हो जाता है।

चीन के पास करीब 2000 से 2100 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास लगभग 550 से 600 के बीच फाइटर जेट हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि सीधे हवाई टकराव की स्थिति में चीन की संख्या आधारित ताकत भारी पड़ सकती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। भारत की वायुसेना केवल संख्या पर नहीं, बल्कि संतुलित संरचना, मल्टी रोल क्षमता और रणनीतिक तैनाती पर आधारित है, जो उसे हर हालात में जवाब देने लायक बनाती है।

इसके अलावा यह भी तथ्य अहम है कि भारत इस अंतर को तेजी से कम करने की दिशा में आक्रामक कदम उठा चुका है। भारत ने फ्रांस के साथ बड़े स्तर पर रक्षा करार करते हुए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, जो विमानवाहक पोतों पर तैनात होंगे और समुद्री युद्ध क्षमता को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही भारत 114 नए मल्टी रोल राफेल लड़ाकू विमानों के बड़े सौदे की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जो वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इतना ही नहीं, फ्रांस के साथ संयुक्त उत्पादन, हेलिकॉप्टर निर्माण और मिसाइल सिस्टम के सह उत्पादन जैसे समझौते भी किए जा रहे हैं, जिससे भारत न केवल अपनी वायु शक्ति बढ़ा रहा है बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वायु शक्ति बढ़ाने के लिए भारत कई अन्य देशों से भी खरीद के मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का युद्ध अनुभव चीन से कहीं अधिक व्यावहारिक है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की बात करें तो भारतीय सेना का अनुभव लद्दाख और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में चीन से कहीं आगे है। यह वह मोर्चा है जहां आंकड़े नहीं बल्कि जमीनी हकीकत जीत तय करती है।

इसके अलावा, जमीनी युद्ध की स्थिति में हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक किला बन जाता है। चीन की भारी सेना और उपकरण इस इलाके में उतने प्रभावी नहीं रह जाते जितने खुले मैदान में होते हैं। भारतीय सेना ने दशकों तक इन परिस्थितियों में खुद को ढाला है, जबकि चीन को इस तरह की चुनौतियों का सीमित अनुभव है।

वहीं तोपखाने और तैनाती की बात करें तो भारत की स्थिति कई मामलों में मजबूत है। ऊंचाई पर तेजी से हथियार पहुंचाने और उन्हें संचालित करने की क्षमता भारत की बड़ी ताकत है।

नौसेना के क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। चीन की नौसेना आकार में बड़ी है, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक बढ़त देती है। हिंद महासागर में भारत का प्रभाव चीन के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। भारत के पास विमानवाहक पोत हैं और समुद्री मार्गों पर उसकी पकड़ मजबूत है। युद्ध की स्थिति में यह क्षेत्र चीन की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है।

अब बात आती है आधुनिक युद्ध की, जहां असली खेल साइबर और अंतरिक्ष में हो रहा है। इस क्षेत्र में चीन ने तेजी से बढ़त बनाई है। साइबर हमले, उपग्रह तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में चीन आगे है। भारत ने इस दिशा में कदम जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन अभी काफी दूरी तय करनी बाकी है। यही वह क्षेत्र है जो आने वाले समय में युद्ध की दिशा तय करेगा।

देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से यह मुकाबला केवल दो देशों के बीच नहीं है। यह पूरे एशिया में शक्ति संतुलन की लड़ाई है। भारत अब केवल सीमा की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएं और वैश्विक साझेदारियां इस दिशा में साफ संकेत देती हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र प्रथम नीति ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। इस नीति का सीधा असर रक्षा क्षेत्र में दिख रहा है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद उत्पादन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीमा क्षेत्रों में सड़कों और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास, सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना इस नीति के प्रमुख स्तंभ हैं। इसका परिणाम यह है कि भारत अब जवाबी रणनीति अपनाने की स्थिति में आ चुका है।

बहरहाल, यह एक तथ्य है कि चीन अभी भी संसाधनों, बजट और तकनीक में आगे है। लेकिन भारत ने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना शुरू कर दिया है। भूगोल, अनुभव और रणनीतिक सोच भारत को इस मुकाबले में मजबूती देते हैं। अगर टकराव होता है तो यह एकतरफा नहीं होगा। भारत अब वह देश नहीं है जो दबाव में झुक जाए। यह एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो चुनौती को स्वीकार करता है और जवाब देने की क्षमता रखता है। डोकलाम और गलवान दिखा चुके हैं कि भारत अब चीन के मुकाबले में पीछे नहीं, बल्कि बराबरी पर खड़ा है।

# जिम्मेदारों का गैरजिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार

**जहां तक एलपीजी की बात है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समय था जब एलपीजी कनेक्शन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। सामान्य परिस्थितियों में भी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों से भी दो चार होना पड़ता था। धरातल पर देखेंगे तो हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आज 31.3 मिलियन टन एलपीजी गैस की खपत है।**

विरोध के नाम विरोध या सत्ता के लालच में राष्ट्र-हित के नकार का कोई उदाहरण मिल सकता है तो वह हमारे देश में ही मिल सकता है। आज जब समूची दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है और अमेरिका व ईरान युद्ध के दुष्परिणामों से दुनिया के लगभग सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित हो रहे हैं उस दौर में देश में अराजकता का माहौल बनाये जाने के प्रयासों को किसी भी हालात में

सचिन तोमर

स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समझ में नहीं आता कि देश में भय और अराजकता का माहौल बनाने से क्या हासिल हो सकेगा। आज दुनिया के देशों की एक दूसरे पर निर्भरता अधिक बढ़ी है। ऐसे में दुनिया के किसी भी कौने में कोई अप्रिय घटनाएं घटित होती है तो उसका प्रभाव कमोबेस दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता है। सबको मालूम है कि कच्चे तेल और एलपीजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कोई आज की बात नहीं है। यह कोई हमारे देश की ही समस्या हो ऐसा भी नहीं है। बल्कि हार्मुज जलडमरुमध्य से जल यातायात को बाधित होने से यह समस्या और

अधिक बढ़ी है। यह भी मालूम है कि ताजिंदगी के लिए किसी भी वस्तु की किसी भी देश द्वारा संग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि एलपीजी के हालिया संकट की ही बात की जाये तो होना तो यह चाहिए था कि ऐसे संकट के दौर में पक्ष-विपक्ष एक साथ खड़ा होता और ऐसे हालातों में आमजनता को पेनिक करने के स्थान पर हालात से निपटने में सहभागी बनते तो एक जिम्मेदार पक्ष-विपक्ष या आम नागरिक की बात होती। पर हमने तो हालात ऐसे बना दिए जैसे एलपीजी का अकाल आ गया हो और चारों तरफ आंदोलन-प्रदर्शन के हालात बनाकर जमाखोरों को प्रोत्साहित करने और आमजन में भय का वातावरण बना दिया। जिसके घर में एलपीजी का सिलेण्डर था भी वह भी एक और सिलेंडर लाने की दौड़ में लग गया और इससे हालात बनने के स्थान पर बिगड़ने वाले होने लगे। होना तो यह चाहिए था कि विपक्षी भी सरकार के साथ खड़े होकर एक और आम जनता को हालात से निपटने के लिए प्रेरित करते वहीं दूसरी और ऐसे समन्वित प्रयास किये जाते जिससे विदेशों से एलपीजी लाने में आ रही दिक्कतों का हल खोजा जा सकता।

गैरजिम्मेदारान हरकत तो इसी से समझा जा सकता है कि सरकार के प्रयासों से जब एलपीजी के दो जहाज होर्मुज जलडमरुमध्य से आने लगे तो यहां तक कहा जाने लगा कि इन जहाजों पर झण्डा अवश्य भारत का है पर इनमें उपलब्ध एलपीजी तो किसी अन्य देश के लिए है। धरने प्रदर्शन और हालात को बदतर बनाने के प्रयास किसी भी हालत में देशहित या देशवासियों के हित में नहीं कहे जा सकते। भले ही यह समझते हो कि हम देशवासियों के हित में सरकार को घेर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह सरकार को घेरना नहीं अपितु देश के प्रति अपने दायित्वों से हटने और पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना गतिविधि ही कही जानी चाहिए।

यह वहीं भारत देश है जब लाल बहादुर शास्त्री के समय अन्न संकट आया तो एक आ'ान पर छोटे बड़े सभी ने एक दिन सोमवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया। पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग आज भी उस आ'ान के चलते आज भी सोमवार का व्रत करते हुए मिल जाएंगे। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1971 के बांग्लादेश के युद्ध के समय समूचा देश इन्दिरा गांधी के साथ एक स्वर में स्वर मिला रहा था। आज पता नहीं ऐसे हालात कैसे होने लगे हैं कि ऑपरेशन सिन्दुर, सर्जिकल स्ट्राइक या अन्य सैन्य गतिविधियों पर भी प्रश्न उठाये जाने लगे हैं। संभवतः दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की बात नहीं होती होगी।

जहां तक एलपीजी की बात है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समय था जब एलपीजी कनेक्शन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। सामान्य परिस्थितियों में भी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों से भी दो चार होना पड़ता था। धरातल पर देखेंगे तो हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आज 31.3 मिलियन टन एलपीजी गैस की खपत है। देश में 31 करोड़ सक्रिय एलपीजी धरेलू कनेक्शन है। समूचे देश की बात की जाए तो प्रतिदिन ओसतन 50 से 60 लाख एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता होती है। ऐसे में मांग और आपूर्ति बनाये रखना अपने आप में दुष्कर है पर हालिया संकट को अलग कर दिया जाए तो पिछले कुछ सालों से एलपीजी या पेट्रोल आदि को लेकर देश में किसी तरह का संकट देखने को नहीं मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार्मुज जलडमरुमध्य से दो जहाज भारतीय तट पर पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा भारतीय जहाजों को निर्बाध रुप से रास्ता दिलाने के प्रयास जारी है। ऐसे हालातों के बावजूद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना बड़ी बात है। इस संकट के दौर में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व हो जाता है। हालात हमारे सामने हैं, सरकार के प्रयास भी हमारे सामने हैं, ऐसे में जमाखोरी और कालाबाजारी को निरुत्साहित करना हम सबका दायित्व होना चाहिए। आवश्यकता नहीं होने पर भी जबरदस्ती सिलेण्डर का स्टॉक करने से बचना चाहिए। वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने में सहभागी बनना चाहिए। जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक जबरदस्ती पेनिक होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे तत्व जो हालात को व्यवस्थित करने के स्थान पर बिगाडने व पेनिक करने व जमाखोरी और कालाबाजारी को प्रोत्साहित कर रहे हो उन्हें बेनकाब करने के लिए आगे आना होगा। यदि ऐसे दौर में हमें एक जुट होना होगा और राष्ट्रहित को ही सर्वोपरी मानना होगा।

# विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया

## विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया

# भारत के लिए अग्निपरीक्षा का समय

इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि जब कूटनीति की मेज से आवाजें कम और आकाश में विमानों की गड़गड़ाहट ज्यादा होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि युद्ध निकट है। और इस बार तो समंदर में भी भीषण तूफान उठ रहा है। दुनिया फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। 27 फरवरी 2026 का दिन वैश्विक इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है, जहाँ से वापसी का रास्ता धुंधला पड़ता जा रहा है। जब युद्ध के बादल गहराते हैं, तो सबसे पहले दूतावास खाली होते हैं और आसमान में लड़ाकू विमानों की कतारें दिखने लगती हैं। आज ठीक यही हो रहा है।

संजीव कुमार

अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने तेल अवीव से जो एग्जिट ईमेल भेजा, वह केवल एक प्रशासनिक संदेश नहीं, बल्कि आने वाले महाविनाश का सायरन है। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की आशंका ने बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी है। उधर, दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत, यूएसएस गेराल्ड आर.फोर्ड, हैफा के तट पर लंगर डाल चुका है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब ₹धमकी₹ का समय समाप्त हो चुका है और ₹कार्रवाई₹ की घड़ी आ गई है। एक भी चूक हुई तो केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के इस युद्ध में कूदने और परमाणु युद्ध तक पहुंचने का खतरा है।

युद्धाभ्यास से युद्ध की दहलीज तक - बीते कुछ हफ्तों की समयरेखा को देखें तो स्पष्ट होता है कि स्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं। विगत एक फरवरी 2026 को मास्को, बीजिंग और तेहरान

के बीच हुए एक त्रिपक्षीय सामरिक समझौते ने पश्चिम की नींद उड़ा दी है। यह केवल रक्षा समझौता नहीं था, बल्कि रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव द्वारा परिकल्पित उस बहुध्रुवीय विश्व की घोषणा थी, जो अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार है। 43 पन्नों के इस समझौते के महज इतने ही बिंदु सामने आये हैं, जिसमें युद्ध होने की स्थिति में एक दूसरे को आर्थिक और संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक सहयोग और समर्थन देने की बात की गयी है। पर दुनिया जानती है कि कड़ी बातें कहना वैसे ही होता है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं और खामोशी की गहराई समंदर से गहरी होती है। दुनिया की यह खामोशी ज्यादा खतरनाक है। इसके तुरंत बाद 16 फरवरी 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन है, वहां मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट-2026 अभ्यास शुरू हुआ। रूस और चीन के युद्धपोत ईरान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यह महज कोई सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि उस भू-राजनीतिक विस्फोटक का अंतिम फ्यूज है, जिसे सुलगाने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। यह संदेश साफ है कि अगर फारस की खाड़ी में युद्ध हुआ, तो ईरान अकेला नहीं होगा।

सवाल अब यह नहीं रह गया है कि धमाका होगा या नहीं, अब सवाल यह है कि इस महायुद्ध की पहली चिंगारी कहाँ गिरेगी और क्या कोई ऐसी शक्ति शेष है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्ठी में झोंकने से बचा सके? 19 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम आया कि ईरान के पास केवल 10 से 15 दिन हैं। उनकी भाषा स्पष्ट थी, ₹या तो डील करो, या तबाही के लिए तैयार रहो।₹ ईरान समझौते के लिए तो तैयार है, पर अमेरिका जो शर्तें रख रहा है, वह मानने को

तैयार नहीं।

**परमाणु गतिरोध:** वियना वार्ता का डेड एंड और इसीलिए 26-27 फरवरी 2026 को जिनेवा में अंतिम दौर की वार्ता बेनतीजा रही। जिनेवा में चली पांच घंटे की मैराथन बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर तो ओमान ने इसे प्रगति बताया, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत यह है कि ईरान ने अपनी संप्रभुता और परमाणु अधिकारों के साथ समझौता करने से मना कर दिया है। यानी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं (फोर्डो, नतांज और अराक) को पूरी तरह नष्ट कर दे और समृद्ध यूरेनियम देश से बाहर भेज दे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची का तर्क अडिग है परमाणु ऊर्जा हमारा अधिकार है, और हम प्रतिबंधों की बंदूक के साये में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

**फोर्ड की तैनाती:** इजराइल बनेगा लॉन्च पैड? - यूएसएस गेराल्ड आर.फोर्ड का इजराइल पहुँचना रणनीतिक रूप से एक चेकमेट की चाल जैसा है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने दो सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोतों को तैनात कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में है और फोर्ड अब हैफा में। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि फोर्ड की उपस्थिति इजराइल को वह सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिसके बाद वह ईरान पर प्री-एम्प्टिव यानी निवारक हमला कर सकता है। फोर्ड का अत्याधुनिक एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइली शहरों को ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाएगा, जबकि उसके डेक से उड़ने वाले इ-35 विमान ईरान के परमाणु ठिकानों को जमींदोज करने की क्षमता रखते हैं। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की साठियता बताती है कि अमेरिका शायद खुद सामने न आकर इजराइल को आगे कर दे। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता ने भी साफ कर दिया है कि यदि उनके देश पर एक भी मिसाइल गिरी, तो इजराइल का अस्तित्व इतिहास के पन्नों तक सीमित कर दिया जाएगा।

**ईरान से निकासी की भगदड़-** कूटनीति की हार -इतिहास बताता है कि जब सरकारें अपने नागरिकों को घर वापस बुलाने लगती हैं तो यह मान लेना चाहिए कि खुफिया एजेंसियों को युद्ध की निश्चित तारीख पता चल चुकी है। 27 फरवरी को अमेरिकी दूतावास ने गैर-जरूरी कर्मचारियों को तुरंत इजराइल छोड़ने को कहा। राजदूत हकाबी के शब्द 'आज ही चले जाइए' दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की बेबसी और तैयारियों को बयां करते हैं। वहीं, चीन जो आमतौर पर बहुत सधी हुई प्रतिाढिया देता है, उसने भी अपने नागरिकों को ईरान से जल्द से जल्द निकलने की सलाह देकर यह पुख्ता कर दिया है कि खाड़ी की आग बुझने वाली नहीं है। ट्रंप की समयसीमा 4-5 मार्च को खत्म हो रही है। अगले हफ्ते वियना में होने वाली तकनीकी वार्ता शायद केवल एक

औपचारिकता बनकर रह गई है। दुनिया के पास अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं, जब हथियार बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि इस बार कोई गीदड़भभकी नहीं दे रहा।

**फारस की खाड़ी में अभूतपूर्व सैन्य जमावड़ा** – अमेरिका ने मध्य पूर्व में हाल के दशकों का सबसे बड़ा नौसैनिक जमावड़ा खड़ा कर दिया है। इस वक्त फारस की खाड़ी और अरब सागर में कम से कम 16 अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। इनमें दो परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड शामिल हैं, जिनमें से हर एक करीब 70 लड़ाकू विमान ले जा सकता है।

**हवा में ताकत और भी खतरनाक** – जॉर्डन के मुवाफ्फक सल्ती एयर बेस और सऊदी अरब के अल-खार्ज बेस पर एफ-35 स्टेल्थ फाइटर्स, ए-10सी अटैक विमान, एमक्यू-9 ड्रोन और तीन ई-11ए बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशन नोड तैनात किए गए हैं। यह संख्या जून 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से भी ज्यादा है।

**कम नहीं है ईरान की भी तैयारी** – रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास 1500 से ज्यादा छोटी, तेज रफ्तार हमला नौकाओं का मॉस्किटो फ्लीट है, जो 110 नॉट्स की रफ्तार से दौड़ सकती हैं और संख्या के बल पर अमेरिकी रडार को धोखा दे सकती हैं। उनके पास नस्र, कौसर (25 किमी रेंज), गादेर (200-300 किमी) और अबू महदी (1000 किमी से ज्यादा) जैसी एंटी-शिप मिसाइलें हैं, जो खाड़ी के उथले पानी (औसत गहराई 35-50 मीटर) से दागी जा सकती हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी युद्धपोत समुद्र की तह में भेज दिए जाएंगे।

और अब जरा सोचिए अगर यह टकराव हुआ, तो क्या सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित रहेगा? नहीं, यह तो पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक देगा। सबसे पहला और सीधा निशाना होगा होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से दुनिया का 20 फीसदी तेल गुजरता है। ईरान ने पहले ही इसे बंद करने की धमकी दे रखी है। एक बार यह रास्ता बंद हुआ, तो वैश्विक तेल कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल के पार जाएंगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी ठिकाने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस, अल-खार्ज, ओमान के दुकम एयरपोर्ट, जॉर्डन के मुवाफ्फक सल्ती, कतर के अल-उदीद, सभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों की जद में हैं। इन ठिकानों से जुड़े सभी नागरिक एयरपोर्ट, दुबई, अबू धाबी, दोहा, मनामा, कुवैत सिटी, रियाद तुरंत बंद करने होंगे, क्योंकि कोई भी यह जोखिम नहीं लेगा कि एक भी यात्री विमान गलती से भी मिसाइल हमले की चपेट में आ जाए। इजरायल चाहे भले ही सीधे खाड़ी में न हो, लेकिन नेतन्याहू लगातार ईरान की मिसाइलों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो तेल अवीव उसकी पहली जवाबी कार्रवाई का निशाना बनेगा।

हिज्बुल्लाह (लेबनान), हूती (यमन) और शिया मिलिशिया (इराक, सीरिया) सभी एक साथ अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमला करेंगे। यह कोई द्विपक्षीय झड़प नहीं होगी, यह पूरे पश्चिम एशिया को जलाने वाली आग होगी, जिसमें रूस, चीन, यूरोप और भारत को भी अपनी-अपनी सुरक्षा और तेल आपूर्ति बचाने के लिए कूदना पड़ेगा और तब आप देखेंगे कि इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी।

**वैश्विक महाशक्तियों के बीच भारत की अग्निपरीक्षा-** रूस और चीन के लिए खाड़ी का यह संकट एक अवसर की तरह है। वे चाहते हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में उलझा रहे ताकि पोन और ताइवान पर दबाव कम हो सके लेकिन भारत के लिए यह स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। भारत को 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करनी है, जहाँ ईरान अब एक पूर्ण सदस्य है। दूसरी ओर, क्वाड के साथी अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया है कि वह चाबहार पोर्ट का संचालन बंद करे। भारत ने इस प्रोजेक्ट को फिलहाल स्थगित कर रखा है। चाबहार न केवल भारत का रणनीतिक निवेश है, बल्कि मध्य एशिया तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता भी है। यदि युद्ध छिड़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें 150 डॉलर के पार जा सकती हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती पैदा होगी।

होर्मुज की लहरें इस समय शांत जरूर हैं, लेकिन उनके भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा है। ईरान, रूस और चीन की मैरीटाइम बेल्ट ने पश्चिमी देशों के लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। क्या दुनिया 1914 और 1939 की गलतियों को दोहराने जा रही है? फारस की खाड़ी की तपती रेत पर आज जो इबारत लिखी जा रही है, वह केवल खाड़ी का भविष्य नहीं, बल्कि पूरी मानवता का भाग्य तय करेगी। अगर कूटनीति इस हफ्ते हार गई, तो अगला हफ्ता बारूद की गंध और सायरनों की आवाज के बीच शुरू होगा।

## ट्रंप के विकल्प : विनाश या शांति

राष्ट्रपति ट्रंप के सामने अब तीन रास्ते हैं, और तीनों ही जोखिम से भरे हैं। यदि वे समझौता करते हैं, तो उनकी छवि एक कमजोर नेता की बनेगी। यदि वे पीछे हटते हैं, तो यह अमेरिका के सैन्य सम्मान की ऐतिहासिक हार होगी। और यदि वे युद्ध का चुनाव करते हैं, तो यह एक अंतहीन विनाश का सिलसिला होगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे धकेल देगा।

# आर्थिक आपदा बनता युद्ध, विश्व की अर्थव्यवस्था के समक्ष खतरा

अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए ईरान पर जो हमला किया, वह अमेरिकी कानूनों के हिसाब से भी अवैधानिक है। इस युद्ध के कारण विश्व में गैस और तेल का जो संकट पैदा गया है, उसके समाधान का कोई उपाय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास नहीं दिखता। लगता है उन्होंने इस पर कोई विचार ही नहीं किया कि ईरान पर हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति में जो बाधाएं खड़ी होंगी, उनसे कैसे निपटा जाएगा।

ईरान इजरायल के साथ खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डों पर भी हमले कर रहा है और उसने होर्मुज समुद्री मार्ग को भी बाधित कर रखा है, जहां से 20-30 प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ईरान ने होर्मुज मार्ग बंद करने और इस चेतावनी के बाद कि दुनिया 200 डालर प्रति बैरल तक तेल खरीदने के लिए तैयार रहे, यह कहा

अनिल वशिष्ठ

कि यहां से निकलने वाले जहाजों को हमारी नौसेना को सूचित करना होगा, लेकिन जब तक इस मार्ग से गैस और तेल की आपूर्ति निर्बाध ढंग से नहीं होने लगती, तब तक ऊर्जा संकट के समाधान को लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता। चूंकि खाड़ी देश तेल-गैस की आपूर्ति होर्मुज से करते हैं, इसलिए वे ईरान के रवैये पर निर्भर हैं। स्वाभाविक रूप से भारत और चीन जैसे देशों को होर्मुज मार्ग बाधित होने से खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि वे अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए एक बड़ी हद तक खाड़ी के देशों पर आश्रित हैं। यह राहत की बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के बाद ईरान ने संकेत दिए कि वह भारत के जहाजों को होर्मुज से आने देगा।

नई दिल्ली में ईरान के राजदूत ने भी भारत को मित्र देश बताते हुए ऐसे ही सकारात्मक संकेत दिए और दो भारतीय जहाजों को इस जल मार्ग से आने की इजाजत मिल भी गई, लेकिन यह अभी साफ नहीं कि भविष्य में सभी भारतीय जहाज होर्मुज से बिना किसी परेशानी के गुजरते रह सकते हैं या नहीं? खाड़ी के देशों में तेल और गैस का उत्पादन प्रभावित होने और वहां से उनकी आपूर्ति बाधित होते ही उनके दाम बढ़ने लगे हैं और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के समक्ष खतरा पैदा हो गया है। यह एक नई आर्थिक आपदा बन रहा है। तेल, गैस, उर्वरकों पर निर्भर तमाम भारतीय उद्योगों के समक्ष भी संकट गहराने लगा है। कुछ तो बंद होने की कगार पर हैं या फिर अपना उत्पादन कम करने को विवश हैं। खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई

रुक जाने से भारत समेत विश्व भर में महंगाई बढ़ने के साथ ही बेरोजगारी पैदा होने का भी खतरा है। इस खतरे के लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ही उत्तरदायी हैं, जिन्होंने अपनी जिद और अहंकार में नतीजों की परवाह किए बिना इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। खाड़ी के देशों से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने से देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल का संकट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रसोई गैस की किल्लत नजर आने लगी है। रेहड़ी वालों से लेकर रेस्त्रां और होटल तथा आम उपभोक्ता उसकी किल्लत बढ़ती देख रहे हैं। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी दावा कर रहे हैं कि तेल एवं गैस की कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरों, कालाबाजारियों के कारण गैस का संकट खड़ा होता दिख रहा है। मुनाफाखोर इस संकट को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। चूंकि गैस संकट पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए आम लोग भी चिंतित हैं। इसका ही नतीजा है कि कई स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियों के सामने लंबी-लंबी लाइनें दिख रही हैं। इससे लोग और अधिक आशंकित हो रहे हैं। विपक्षी दल इस आशंका को और हवा दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है और हालात पर निगरानी के लिए एक समिति गठित कर दी है, पर अभी इन कदमों का सकारात्मक असर नहीं दिख रहा है। यह तब तक नहीं दिखेगा, जब तक राज्य सरकारें गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती नहीं बरततीं। यह अच्छा हुआ कि सरकार ने राज्यों को पीडीएस के तहत अतिरिक्त केरोसिन जारी करने का फैसला किया। ईरान पर और हमले की धमकियों के बीच अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने पर अपनी आपत्ति हटा ली है। यह उसकी मजबूरी को ही दशार्ता है। भारत सरकार रूस से तेल खरीद बढ़ाने के साथ कुछ अन्य देशों से तेल-गैस खरीद के जतन कर रही है, पर जब तक ये सौदे हो नहीं जाते और तेल-गैस आपूर्ति का रास्ता साफ नहीं होता, तब तक राहत की सांस नहीं ली जा सकती। भारत उस वेनेजुएला से भी तेल खरीद रहा है, जहां बीते दिनों अमेरिका ने हमला कर वहां के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया था। निःसंदेह वेनेजुएला में तेल के सबसे अधिक भंडार हैं, पर उनसे तेल का दोहन कठिन है। इस तेल का शोधन भी आसान नहीं। अब इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला पर बिना सोचे-समझे मनमाने तरीके से हमला किया, वैसे ही ईरान पर। तेल संकट दूर करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने इमरजेंसी स्टाक से 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी किया है, लेकिन इसके बाद भी तेल के दाम सौ डालर पार कर गए हैं। चूंकि ईरान जवाबी हमले करने में अभी भी समर्थ बना हुआ है, इसलिए कहना कठिन है कि युद्ध कब खत्म होगा। यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है और उसके चलते खाड़ी के देशों से तेल एवं गैस की आपूर्ति बाधित बनी रहती है तो विश्व में ऊर्जा संकट और गहराएगा। इस ऊर्जा संकट के लिए सबसे बड़ा दोषी अमेरिका ही होगा।

वह इस युद्ध को जल्द खत्म करने में सक्षम नहीं दिख रहा है। उसके अरबों डालर खर्च हो चुके हैं, पर युद्ध जल्द समाप्त होने के कोई संकेत नहीं। अमेरिका ने सोचा था कि अली खामेनेई को मार देने से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिखता। मुश्किल यह भी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई युद्ध खत्म करने के लिए ऐसी शर्तें रख रहे हैं, जिन्हें न तो अमेरिका स्वीकार कर सकता है और न ही खाड़ी के देश।

## भारत को ईरान से सबक लेने की जरूरत

भारत कई मामलों में अमेरिका के दबाव में नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर रूस से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने का मामला। भारत अमेरिका के दबाव में अपने कदम वापस खींच लेता है। जबकि ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था और अब अमेरिका भी इजरायल के साथ युद्ध में कूद गया, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर भी करारा पलटवार किया। अब अमेरिका युद्ध विराम के प्रयासों में जुटा है। अपनी सुप्रीम लीडरशिप को खोने के बाद भी ईरान का मनोबल और इच्छा शक्ति कम नहीं हुई। ईरान ने साफ कर दिया कि वह खत्म होना स्वीकार करेगा, लेकिन झुकना नहीं। अब ईरान अमेरिका और इजरायल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले कर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका युद्ध विराम का रास्ता खोज रहा है, लेकिन ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने कुछ कड़ी शर्तें रख दी हैं। भारत को भी ईरान से सबक लेने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए भारत ने अमेरिका का दबाव स्वीकार किया, हालांकि जाहिर तौर पर भारत इसे नहीं मान रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार कई मंच पर इस बात को कहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री उसका खंडन भी नहीं करते हैं। वहीं, रूस से पेट्रोलियम पदार्थ लेने पर भी भारत अमेरिकी दबाव में नजर आ रहा है। भारत को भी ईरान से सबक लेने की जरूरत है और अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और मनोबल को दिखाने की जरूरत है।

# तेल के अलावा रोजजमर्रा की ये चीजें हो जाएंगी महंगी

इस टकराव का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। पिछले 9 मार्च को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मानक माने जाने वाले ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमतें पहली बार 2022 के बाद 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई थीं। हालांकि उसी दिन ये गिरकर 95 डॉलर से नीचे आ गई थीं, लेकिन बीते कुछ दिनों में तेल टैंकरों पर किए गए नए हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रही है।

## 1. खाना-पीना हो जाएगा महंगा

मौजूदा संघर्ष का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो दुनिया के बड़े उर्वरक (खाद) निर्यातक हैं। आंकड़ों के मुताबिक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के विश्व के चार सबसे बड़े निर्यातक हैं। ये उर्वरक प्राकृतिक गैस से बनते हैं और उन फसलों में इस्तेमाल होते हैं जिनसे दुनिया के करीब आधे खाद्य उत्पाद पैदा होते हैं। हालांकि युद्ध के बावजूद इस क्षेत्र की ज्यादातर उर्वरक कंपनियां अब तक काम करती रही हैं, लेकिन कतर एनर्जी को अपना उत्पादन रोकना पड़ा था। ये यूरिया बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है।

## 2. दवाओं की सप्लाई पर पड़ेगा असर

भारत से होने वाले दवाओं के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा दुबई से होकर गुजरता है। मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध अब दवाओं और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की वैश्विक सप्लाई चेन को भी प्रभावित करने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह दुबई पर हुए हमले हैं। दुबई दुनिया के फार्मा सेक्टर का एक अहम लॉजिस्टिक केंद्र माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे अधिक आबादी वाला इस शहर में दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां 2025 में करीब 9.5 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई थी। यही हवाई अड्डा दवाओं और दूसरे फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बड़ा केंद्र है, खासकर उन दवाओं के लिए जिन्हें ठंडे तापमान यानी 'कोल्ड चेन' में रखना जरूरी होता है। यह हवाई अड्डा भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए खास तौर पर बहुत अहम है।

## 3. मेटल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सप्लाई पर असर

मध्य-पूर्व में चल रही जंग का असर सेमी कंडक्टर और चिप्स के निर्माण पर भी पड़ सकता है जिससे स्मार्टफोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रभावित होंगे। युद्ध का असर अब उन रसायनों और कच्चे माल की आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है, जो औद्योगिक उत्पादन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनमें सल्फर जैसे रासायनिक तत्व और एल्युमिनियम जैसे कच्चे पदार्थ शामिल हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और ईरान उन प्रमुख देशों में शामिल हैं जो सल्फर का निर्यात करते हैं। सल्फर तेल और गैस की रिफाइनिंग के दौरान निकलने वाला एक बाई-प्रोडक्ट होता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे (यूएस जियोलॉजिकल सर्विस) के अनुसार, दुनिया में बनने वाले कुल सल्फेट का लगभग 24 फीसदी हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। इसका इस्तेमाल तांबा और निकल जैसी धातुओं को निकालने में भी होता है, जो आगे चलकर उपकरणों, गाड़ियों, बिजली की ग्रिड, सेमीकंडक्टर, बैटरियों और स्टेनलेस स्टील जैसे कई अहम उत्पादों के निर्माण में काम आती हैं। इस सेक्टर में युद्ध के असर अब साफ दिखाई देने लगे हैं।

# युद्धकाल का संकट, राजनीति और नागरिक कर्तव्य

अरुण शर्मा

युद्धकाल के कारण पूरी दुनिया में आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो जाने के कारण तेल, गैस व अन्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। चीन, जापान, कोरिया जैसे समृद्ध देश और पाकिस्तान, बांग्लादेश व श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 10 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की वृद्धि कर चुके हैं।

अमेरिका-इजराइयल और ईरान युद्ध को प्रारंभ हुए 15 दिन का समय व्यतीत हो चुका है और अभी भी युद्ध का दायरा बढ़ ही रहा है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और आक्रामकता के कारण संपूर्ण विश्व में तेल और गैस की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अन्य आवश्यक उत्पादों के जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। विश्व के तमाम देशों की सरकारें एवं विपक्षी दल कदम से कदम मिलाकर तेल, गैस व ऊर्जा संकट, आर्थिक अनिश्चितता तथा कार्यालयों के पलायन के कारण उत्पन्न हो रहे संकट का सामना कर रहे हैं। सभी देशों में सत्तापक्ष व विपक्ष मिलजुल कर कर रहे हैं वहीं भारत में विपक्ष इस संकट का उपयोग अपने ही देश को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है।

भारत में इस युद्ध तथा उससे उपजे वैश्विक संकट पर अलग ही राजनीति हो रही है। जब से युद्ध आरम्भ हुआ है भारत में लखनऊ से लेकर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले तक अमेरिका-इजराइल के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के लिए आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने पहले कभी भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों निंदा तक नहीं की है। विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल तथा उनके नेता इन प्रदर्शनों को हवा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आदि सरकार की विदेश नीति के खिलाफ अनवरत लेख लिख रहे हैं और किसी न किसी बहाने प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं।

युद्धकाल के कारण पूरी दुनिया में आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो जाने के कारण तेल, गैस व अन्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। चीन, जापान, कोरिया जैसे समृद्ध देश और पाकिस्तान, बांग्लादेश व श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश पेट्रोल व डीजल

की कीमतों में 10 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की वृद्धि कर चुके हैं। कई देशों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है पड़ोसी पाकिस्तान में तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं जबकि भारत मे पेट्रोल व डीजल के दाम काफी स्थिर हैं। भारत में केवल घरेलू रसोई गैस के दामों में ही 60 रुपए की वृद्धि की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध से पैदा हुए संकट पर स्वयं नजर रख रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री मोदी दुनियाभर के नेताओं के साथ संपर्क में हैं तथा आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए नए मार्ग ढूंढ रहे हैं। अभी तक भारत केवल 27 देशों से ही तेल व गैस की खरीदता था किंतु अब 40 देशों के साथ क्रय सम्बन्ध बनाए जा रहे हैं।

विडंबना है कि विपक्ष इस संकट का उपयोग राजनीति के लिए कर रहा है। विपक्षी दल के नेता, आईटी सेल तथा कार्यकर्ता अपने आकाओं की शह पाकर अफवाह बाज बनकर सड़क पर आ गए हैं। बड़े नेता ऊपर संसद ठप कर रहे हैं और छोटे-बड़े जमाखोरों के साथ मिलकर आम जनमानस का पैनिक बटन दबाकर गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी कतारें लगवा रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री मोदी व उनकी सरकार की पहल का ही परिणाम है कि ईरान-अमेरिका-इजरायल जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से दो भारतीय जहाज शिवालिक और नंदादेवी 927000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं। भारत सरकार व अधिकारियों के प्रयास से ही फारस की खाड़ी में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारत के 253 नाविक अब तक सुरक्षित वापस आ चुके हैं। भारत सरकार ऊर्जा आपूर्ति और नागरिक सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों से स्पष्ट कर चुके हैं कि युद्ध का असर आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए।

युद्धकाल में जो लोग भारत की विदेश नीति को फेल बताने वालों को स्मरण रखना चाहिए कि कि जब संघर्ष के कारण उड़ानें प्रभावित होने पर कई ईरानी नागरिक भारत में फंस गए थे भारत ने ही उन्हें ईरान की सहायता से उनके देश पहुँचाया। वहीं युद्ध के बीच 1.72 लाख भारतीय सकुशल भारत वापस आए हैं।

भारत सरकार युद्धकाल में जनता को कोई समस्या न हो इसके लिए लगातार कार्य कर रही है किंतु क्या हम सभी नागरिक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? परिस्थितियां इसका उत्तर नहीं में दे रही हैं। यदि नागरिक भी कर्त्तव्य बोध से बंधे होते तो आज देश में गैस सिलेंडर को लेकर जो पैनिक मचा हुआ है वह न होता। ऊर्जा संकट की आहट मात्र से अफवाह बाज सक्रिय हो गए और ऐसी अफवाहें उड़ाई गई कि जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। जिन घरों मे एक या दो भरे हुए एलपीजी सिलिंडर मौजूद हैं वो भी हल्ला मचा रहे हैं। प्रतिदिन होने वाली सिलिंडर बुकिंग 55 लाख से बढ़कर 75 लाख हो गई। देशभर मे अजीब नजारे देखने को मिल रहे हैं। जो परिवार 853 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदने में भार का अनुभव करते थे अब वही लोग चोर बाजार से 3500 तक का सिलेंडर खरीदने की हैसियत दिखा रहे हैं।

समाज मे नैतिकता व सदाचार की कमी के कारण ही जमाखोरी व कालाबाजारी एक सामाजिक बुराई का रूप ले चुकी है। युद्धकाल में देशवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग कर्तव्य से विमुख होकर अपने लिए मुनाफे का अवसर खोज रहा है। अभी भारत का युद्ध से कोई सबंध नहीं है और यह युद्ध भारत से बहुत दूर हो रहा है तब भी जिस प्रकार का पैनिक भारत में हुआ है वह कुछ भारतीयों की ही विकृत मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है। संकट है किंतु अगर कुछ भी कर्त्तव्य बोध होता तो हालात बिल्कुल सामान्य ही रहते। अंततः अब सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारियों पर कार्यवाई आरम्भ कर दी है और उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं।

ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध अभी काफी लंबा चलने की आशंका है तथा हालात अभी और भी खराब ही हो सकते हैं किन्तु भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके लिए होमुर्ज स्ट्रेट का रास्ता खोला गया है। सरकार अपना काम कर रही है किंतु अब समय आ गया है कि भारतीय नागरिक भी अपने कर्तव्य का पालन करें और पैनिक न हों।

# राजस्थान का 'कश्मीर' माउंट आबू: भीषण गर्मी से राहत के लिए यह है परफेक्ट हिल स्टेशन

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

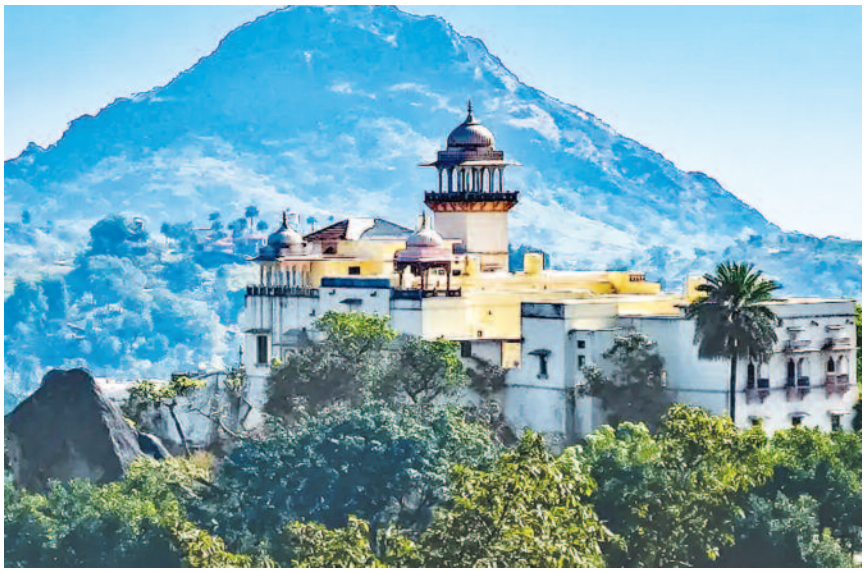

राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। अरावली पर्वतमाला की ऊँचाइयों पर बसा यह सुंदर स्थल अपनी ठंडी जलवायु, हरियाली और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तानी प्रदेश में स्थित होने के बावजूद यहाँ का वातावरण अत्यंत सुहावना और शांतिपूर्ण है, जो पर्यटकों को विशेष आकर्षित करता है।

## प्रमुख दर्शनीय स्थल-

**Nakki Lake-** यह माउंट आबू की सबसे प्रसिद्ध झील है। यहाँ पर्यटक नौकायन का आनंद लेते हैं और झील के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करते हैं। मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था।

**Dilwara Temples-** 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये जैन मंदिर अपनी अद्भुत संगमरमर की नक्काशी के लिए विश्वविख्यात हैं। यहाँ की वास्तुकला और शिल्पकला पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

**Guru Shikhar-** यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी है। यहाँ से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है।

**Sunset Point-** सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। ढलते सूरज की लालिमा पहाड़ियों पर अद्भुत छटा बिखेरती है।

## मौसम और घूमने का सवो

माउंट आबू का मौसम वर्षभर सुहावना रहता है।

**गर्मी (अप्रैल-जून):** तापमान 23°C से 33°C के बीच, घूमने के लिए उत्तम समय।

**मानसून (जुलाई-सितंबर):** हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर।

**सर्दी (अक्टूबर-मार्च):** ठंडा और रोमांटिक मौसम, पर्यटन के लिए सबसे अच्छा समय।

## स्थानीय विशेषताएँ

माउंट आबू में हर वर्ष 'समर फेस्टिवल' का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ की हस्तशिल्प वस्तुएँ और राजस्थानी व्यंजन भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं।

## कैसे पहुँचें?

**सड़क मार्ग:** उदयपुर, अहमदाबाद और जयपुर से बस एवं टैक्सी सुविधा उपलब्ध है।

**रेल मार्ग:** निकटतम रेलवे स्टेशन आबू रोड है।

**वायु मार्ग:** निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है।

माउंट आबू प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा संगम है। यदि आप राजस्थान की गर्मी से राहत पाना चाहते हैं और पहाड़ों की ठंडी वादियों में सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो माउंट आबू एक आदर्श पर्यटन स्थल है।

# वैश्विक संकट के बीच मानवता की अंतिम सुरक्षा-रेखा है ऊर्जा संरक्षण

एन के शर्मा

आज जब विश्व एक बार फिर भू-राजनीतिक तनावों के दौर से गुजर रहा है और ईरान, अमेरिका तथा इजरायल के बीच टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है, तब ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन चुकी है। तेल और गैस के दामों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या आधुनिक सभ्यता ने अपनी बुनियाद अत्यधिक अस्थिर संसाधनों पर खड़ी कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि मानवता की सुरक्षा का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय बनकर उभर रहा है। ऊर्जा आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वह उद्योगों की मशीनें हों, परिवहन के साधन हों, डिजिटल अर्थव्यवस्था हो या घरेलू जीवन की सुविधाएं किंतु विडंबना यह है कि जिस ऊर्जा पर हमारी प्रगति आधारित है, वही अब संकट का कारण बनती जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र की 'एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024' के अनुसार आने वाले दशक में वैश्विक ऊर्जा मांग में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जबकि जीवाश्म ईंधनों के भंडार तेजी से सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में यदि ऊर्जा संरक्षण और दक्षता को प्राथमिकता नहीं दी गई तो भविष्य में ऊर्जा संकट केवल आर्थिक चुनौती नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक अस्थिरता और वैश्विक संघर्षों का कारण भी बन सकता है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य इस खतरे को और स्पष्ट करता है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो रही हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। दरअसल भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में वैश्विक संकट का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। पैट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि केवल परिवहन लागत को नहीं बढ़ाती बल्कि खाद्य पदार्थों से लेकर निर्माण सामग्री तक हर क्षेत्र में महंगाई को जन्म देती है। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है।

भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और यहां ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 'इंडिया एनर्जी आउटलुक 2024' रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में यदि ऊर्जा खपत को संतुलित नहीं किया गया तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को अपनी नीति का केंद्रीय तत्व बनाया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और 'उजाला' जैसे कार्यक्रमों ने यह साबित किया है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण और उससे हुई 48 बिलियन यूनिट बिजली की बचत इस बात का प्रमाण है कि यदि नीति और जनभागीदारी साथ आएं तो ऊर्जा संरक्षण एक जनांदोलन बन सकता है।

ऊर्जा संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी नई तकनीक या बड़े निवेश पर निर्भर नहीं है बल्कि यह हमारे

दैनिक व्यवहार में छोटे-छोटे बदलावों से ही संभव है। उदाहरण के लिए, अनावश्यक रूप से जलती लाइटों को बंद करना, ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना, एयर कंडीशनर का सीमित प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन को अपनाना और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना, ये सभी कदम न केवल ऊर्जा बचाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। यदि भारत का प्रत्येक परिवार प्रतिदिन केवल एक यूनिट बिजली की बचत करे तो यह देश के लिए ऊर्जा क्रांति के समान होगा। ऊर्जा संरक्षण का संबंध केवल बिजली तक सीमित नहीं है बल्कि यह जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन में जल का व्यापक उपयोग होता है और जल की बबार्दी सीधे ऊर्जा की बबार्दी में बदल जाती है। इसी प्रकार, ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। आज जब दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तब ऊर्जा संरक्षण इस दिशा में सबसे प्रभावी हथियार साबित हो सकता है।

अक्षय ऊर्जा इस संकट का दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करती है लेकिन इसकी सफलता भी ऊर्जा संरक्षण पर ही निर्भर करती है। सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्रोतों का विस्तार तभी प्रभावी होगा, जब ऊर्जा की कुल मांग को नियंत्रित किया जाए। भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और स्मार्ट ग्रिड जैसी तकनीकें इस दिशा में नई संभावनाएं खोल रही हैं लेकिन इन सबका मूल आधार ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही है।

शहरीकरण के बढ़ते दबाव ने भी ऊर्जा खपत को तेजी से बढ़ाया है। महानगरों में ऊंची इमारतें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बढ़ती वाहन संख्या ऊर्जा की मांग को कई गुना बढ़ा देती है। ऐसे में हरित भवन निर्माण, सौर पैनलों का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है। यदि भवन निर्माण में ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दी जाए तो बिजली की खपत में 30 से 40 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। यह न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

ऊर्जा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने से उत्पादन लागत में कमी आती है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा संरक्षण को केवल सरकारी नीति या अभियान के रूप में न देखा जाए बल्कि इसे एक सामाजिक संस्कृति के रूप में विकसित किया जाए। विद्यालयों में ऊर्जा शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, मीडिया के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाई जाए और प्रत्येक नागरिक को यह समझाया जाए कि ऊर्जा की बचत केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब तक ऊर्जा संरक्षण हमारी आदत नहीं बनेगा, तब तक किसी भी नीति या तकनीक का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकेगा। वैश्विक ऊर्जा संकट के इस दौर में भारत के पास एक अवसर भी है, एक ऐसे मॉडल के रूप में उभरने का, जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित कर सके। यदि भारत ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा और तकनीकी नवाचार के समन्वय से आगे बढ़ता है तो वह न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है बल्कि विश्व के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है। यह समझना आवश्यक है कि ऊर्जा का संकट केवल संसाधनों का संकट नहीं है बल्कि यह हमारी सोच और व्यवहार का संकट भी है। यदि हम ऊर्जा को अनमोल संसाधन मानकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना सीख लें तो न केवल वर्तमान संकट से उबर सकते हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध दुनिया भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण कोई जटिल विज्ञान नहीं बल्कि एक सरल जीवनशैली है और यही जीवनशैली आज धरती को बचाने की सबसे प्रभावी चाबी बन चुकी है।

# जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता

मनोज शर्मा

भारत आज दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 2024 में भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ को पार कर गई है। यह एक ऐसी समस्या है जो देश के विकास, संसाधनों, पर्यावरण और लोगों के जीवन स्तर पर सीधा असर डालती है। एक तरफ जहाँ देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी उस तरक्की को खा जा रही है। सड़कों पर भीड़, अस्पतालों में लंबी कतारें, स्कूलों में जगह की कमी और बेरोजगारी– ये सब बढ़ती जनसंख्या के प्रत्यक्ष परिणाम हैं।

**बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम:** गरीबी और भुखमरी: जब किसी परिवार में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले दस, तो गरीबी अपने आप आ जाती है। यही बात पूरे देश पर लागू होती है। भारत में उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ रही है। नतीजा यह होता है कि प्रति व्यक्ति आय कम रह जाती है। करोड़ों लोग आज भी दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। गरीबी का सीधा संबंध अधिक जनसंख्या से है।

**बेरोजगारी :** हर साल लाखों युवा पढ़-लिखकर नौकरी ढूँढने निकलते हैं, लेकिन नौकरियाँ उतनी तेजी से नहीं बढ़तीं जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। एक सरकारी पद के लिए लाखों आवेदन आते हैं। इससे निराशा, अपराध और सामाजिक

# बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम और पारंपरिक भ्रांतियाँ

अस्थिरता बढ़ती है। अगर जनसंख्या नियंत्रित होती तो हर हाथ को काम मिलना आसान होता।

**शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ:** सरकारी स्कूलों में एक कक्षा में 60-70 बच्चे बैठते हैं, जहाँ शिक्षक का ध्यान हर बच्चे पर देना असंभव हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की इतनी भीड़ होती है कि डॉक्टर को एक मरीज को देखने के लिए मुश्किल से दो मिनट मिलते हैं। बढ़ती आबादी के कारण सरकार चाहकर भी हर व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँचा पाती।

**पर्यावरण का विनाश:** ज्यादा लोग यानी ज्यादा जमीन की जरूरत, ज्यादा पानी की खपत, ज्यादा प्रदूषण और ज्यादा कचरा। जंगल काटकर बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, भूजल का स्तर गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों को साफ पानी और स्वच्छ हवा भी नसीब नहीं होगी।

**आवास और शहरीकरण की समस्या:** शहरों में जगह कम पड़ रही है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग तंग और अस्वच्छ जगहों पर रहने को मजबूर हैं। ट्रैफिक जाम, पानी की कमी और बिजली की समस्या – ये सब अधिक जनसंख्या का ही नतीजा है।

**अपराध और सामाजिक अशांत:** जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होतीं तो अपराध बढ़ता है। भूख, बेरोजगारी और निराशा लोगों को गलत रास्ते पर धकेलती है। अधिक जनसंख्या वाले इलाकों में चोरी, लूट और हिंसा की घटनाएँ ज्यादा देखी जाती हैं।

**जनसंख्या नियंत्रण के उपाय:** जनसंख्या नियंत्रण कोई कठिन काम नहीं है, बस इसके लिए जागरूकता और इच्छाशक्ति चाहिए। सबसे पहले शिक्षा का प्रसार जरूरी है, खासकर लड़कियों की शिक्षा। जो परिवार शिक्षित होते हैं, वे खुद समझ जाते हैं कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। परिवार नियोजन के साधनों को गाँव-गाँव तक पहुँचाना जरूरी है। सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए जो धार्मिक भ्रांतियों को दूर करें। महिला सशक्तिकरण भी जनसंख्या नियंत्रण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है – जब महिलाएँ आत्मनिर्भर होती हैं तो वे अपने शरीर और अपने परिवार के बारे में सही फैसले लेती हैं।

**निष्कर्ष :** बढ़ती जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण विनाश और सामाजिक अशांति की जड़ है। पारंपरिक मान्यताएँ जैसे संतान से मोक्ष, बेटे की अनिवार्यता, ज्यादा बच्चे ज्यादा सहारा – ये सब भ्रम हैं जिनका कोई तार्किक या धार्मिक आधार नहीं है। असली धर्म यह है कि जो बच्चे हैं उनकी अच्छी परवरिश हो, उन्हें शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और एक सम्मानजनक जीवन मिले। यह तभी संभव है जब परिवार छोटा हो।

हमें पुरानी सोच को बदलना होगा। मोक्ष संतानों की संख्या से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं है। बुढ़ापे का सहारा ज्यादा बच्चे नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार वाले बच्चे होते हैं। परिवार नियोजन पाप नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और समझदार कदम है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे, तब तक न तो हमारा परिवार खुशहाल होगा और न ही हमारा देश। छोटा परिवार, सुखी परिवार – यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है।

# मर्यादा, सुशासन और शांति के विश्वनायक श्रीराम

**श्रीराम का जीवन हमें सबसे पहले मयार्दा का संदेश देता है। आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी समस्या मयार्दा का संकट है-राजनीति में मयार्दा नहीं, समाज में मयार्दा नहीं, परिवार में मर्यादा नहीं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी मयार्दा नहीं। श्रीराम का जीवन बताता है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मयार्दा होती है।**

रवि जैन

रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पुण्य और पवित्र अवसर है। आज जब दुनिया युद्ध, हिंसा, आतंक, असहिष्णुता, पारिवारिक विघटन, राजनीतिक अविश्वास और नैतिक पतन जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रही है, तब मयार्दा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन-दर्शन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि मानव समाज और विश्व-राजनीति के लिये मार्गदर्शन का स्रोत बन सकता है। श्रीराम का जीवन केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि वह शासन, समाज, परिवार, युद्ध, कूटनीति, न्याय और मानव संबंधों का एक संपूर्ण दर्शन है, जिसे आधुनिक संदर्भों में पुनर्पाठ की आवश्यकता है। श्रीराम का सम्पूर्ण जीवन विलक्षणताओं एवं विशेषताओं से ओतप्रोत है, प्रेरणादायी है। उन्हें अपने जीवन की खुशियों से बढकर लोक जीवन की चिंता थी, तभी उन्होंने अनेक तरह के त्याग के उदाहरण प्रस्तुत किये। राजा के इन्हीं आदर्शों के कारण ही भारत में रामराज्य की आज तक कल्पना की जाती रही है। श्रीराम के बिना भारतीय समाज की कल्पना संभव नहीं है। अब श्रीराम मन्दिर के रूप में एक शक्ति एवं सिद्धि स्थल बन गया है, जो रामराज्य के सुदीर्घ काल के सपने को आकार देने का सशक्त एवं सकारात्मक वातावरण भी बनेगा। श्रीराम मंदिर जीवनमूल्यों की महक एवं प्रयोगशाला के रूप में उभरेगा। क्योंकि श्रीराम का चरित्र ही ऐसा है जिससे न केवल भारत बल्कि दुनिया में शांति, अहिंसा, अयुद्ध, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं अमन का साम्राज्य स्थापित होगा। ईरान-इजरायल एवं यूक्रे-रूस के बीच चल रहा युद्ध एवं इस परिप्रेक्ष्य में विश्वयुद्ध की संभावनाओं को देखते हुए श्रीराम के जीवन आदर्शों को विश्व व्यापी बनाने की अपेक्षा है, ताकि दुनिया शांति एवं चैन से जी सके।

श्रीराम का जीवन हमें सबसे पहले मयार्दा का संदेश देता है। आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी समस्या मयार्दा का संकट है-राजनीति में मयार्दा नहीं, समाज में मयार्दा नहीं, परिवार में मयार्दा नहीं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी मयार्दा नहीं। श्रीराम का जीवन बताता है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मयार्दा होती है। उन्होंने सामर्थ्य होते हुए भी राज्य के लिये संघर्ष नहीं किया, बल्कि पिता की आज्ञा और समाज की मयार्दा को सर्वोच्च माना। आज यदि विश्व राजनीति में मयार्दा और नैतिकता का समावेश हो जाये, तो अनेक युद्ध स्वतः समाप्त हो सकते हैं। राष्ट्र यदि केवल शक्ति और विस्तारवाद की नीति छोड़कर मयार्दा और न्याय की नीति अपनाएं, तो विश्व शांति संभव हो सकती है। आज दुनिया के अनेक युद्ध चाहे वह रूस-यूक्रेन युद्ध हो, मध्य-पूर्व के संघर्ष हों या अन्य क्षेत्रीय युद्ध-इन सबके मूल में

अहंकार, विस्तारवाद, संसाधनों पर अधिकार और वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई है। श्रीराम का युद्ध दर्शन इससे बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने कभी युद्ध को लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि युद्ध उनके लिये अंतिम विकल्प था। उन्होंने पहले संवाद किया, फिर दूत भेजा, फिर समझौते का प्रयास किया और अंत में जब सभी रास्ते बंद हो गये तब युद्ध किया। यह युद्ध नीति आज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिये एक आदर्श मॉडल हो सकती है-पहले संवाद, फिर कूटनीति, फिर प्रतिबंध और अंत में युद्ध। आधुनिक विश्व यदि इस क्रम को स्वीकार कर ले, तो युद्धों की संख्या कम हो सकती है।

श्रीराम का जीवन सुशासन का भी आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसे आज 'रामराज्य' के रूप में जाना जाता है। रामराज्य का अर्थ केवल धार्मिक राज्य नहीं, बल्कि न्याय, समानता, सुरक्षा, समृद्धि और नैतिक शासन व्यवस्था है। रामराज्य में राजा और प्रजा के बीच दूरी नहीं थी, शासन उत्तरदायी था, न्याय त्वरित था, समाज में भय नहीं था और आर्थिक असमानता अत्यधिक नहीं थी। आज लोकतंत्र होने के बावजूद जनता और शासन के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, राजनीति सेवा से अधिक सत्ता का माध्यम बनती जा रही है। श्रीराम का शासन हमें बताता है कि शासन का उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र यदि रामराज्य की अवधारणा से प्रेरणा ले, तो लोकतंत्र अधिक मानवीय और उत्तरदायी बन सकता है।

श्रीराम का जीवन पारिवारिक मूल्यों का भी अद्भुत उदाहरण है। आज दुनिया में परिवार टूट रहे हैं, पीढ़ियों के बीच संवाद समाप्त हो रहा है, रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते जा रहे हैं। श्रीराम ने पुत्र के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, भाई के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, पति के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया और मित्र के रूप में भी आदर्श प्रस्तुत किया। भरत और राम का संबंध त्याग और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। आज यदि परिवारों में अधिकार की जगह कर्तव्य और स्वार्थ की जगह त्याग की भावना आ जाये, तो समाज की आधी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।

श्रीराम ने मयार्दा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता-पिता, यहां तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार, आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीराम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परम्परा प्रान जाहुं बरु बचनु न जाई की थी। श्रीराम हमारी अनंत मयार्दाओं के प्रतीक

पुरुष हैं इसलिए उन्हें मयार्दा पुरुषोत्तम के नाम से पुकारा जाता है। हमारी संस्कृति में ऐसा कोई दूसरा चरित्र नहीं है जो श्रीराम के समान मर्यादित, धीर-वीर, न्यायप्रिय और प्रशांत हो। वाल्मीकि के श्रीराम लौकिक जीवन की मयार्दाओं का निर्वाह करने वाले वीर पुरुष हैं। उन्होंने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध किया और लोक धर्म की पुनःस्थापना की। लेकिन वे नील गगन में दैदीप्यमान सूर्य के समान दाहक शक्ति से संपन्न, महासमुद्र की तरह गंभीर तथा पृथ्वी की तरह क्षमाशील भी हैं।

वे दुराचारियों, यज्ञ विध्वंसक राक्षसों, अत्याचारियों का नाश कर लौकिक मयार्दाओं की स्थापना करके आदर्श समाज की संरचना के लिए ही जन्म लेते हैं। आज ऐसे ही स्वस्थ समाज निर्माण की जरूरत है। सामाजिक दृष्टि से भी श्रीराम का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज के सबसे निम्न माने जाने वाले लोगों को भी सम्मान दिया। केवट, शबरी, जटायु, सुग्रीव, हनुमान-ये सभी समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि थे। श्रीराम ने सभी को साथ लेकर संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। यह सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण है। आधुनिक राष्ट्र निर्माण में भी यही सिद्धांत लागू होता है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर ही राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है। केवल आर्थिक विकास से राष्ट्र महान नहीं बनता, सामाजिक समरसता और नैतिक एकता से राष्ट्र महान बनता है।

श्रीराम हमारे कण-कण में समाये हैं, हमारी जीवनशैली का अभिन्न अंग हैं। श्रीराम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि एक आदर्श राष्ट्र केवल सेना और अर्थव्यवस्था से नहीं बनता, बल्कि चरित्र से बनता है। यदि नागरिक चरित्रवान होंगे, तो राष्ट्र स्वतः शक्तिशाली होगा। आज राष्ट्र शक्ति का अर्थ केवल सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति माना जाता है, जबकि श्रीराम का जीवन बताता है कि नैतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। रावण के पास अधिक सेना, अधिक धन, अधिक विद्या और अधिक शक्ति थी, फिर भी उसकी हार हुई क्योंकि उसके पास नैतिक शक्ति नहीं थी। यह आज के विश्व के लिये बहुत बड़ा संदेश है। आज जब दुनिया अस्तित्व के संकट, पर्यावरण संकट, युद्ध संकट और नैतिक संकट से जूझ रही है, तब श्रीराम का जीवन मानवता को संतुलन का संदेश देता है-शक्ति और शांति का संतुलन, अधिकार और कर्तव्य का संतुलन, भोग और त्याग का संतुलन, राज्य और समाज का संतुलन, परिवार और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। यही संतुलन ही मानव सभ्यता को बचा सकता है।

रामनवमी का पर्व हमें केवल पूजा करने का संदेश नहीं देता, बल्कि श्रीराम के जीवन को अपने जीवन, समाज और राष्ट्र की नीति में उतारने का संदेश देता है। यदि विश्व राजनीति श्रीराम की युद्ध नीति से प्रेरणा ले, यदि लोकतंत्र श्रीराम के सुशासन से प्रेरणा ले, यदि परिवार श्रीराम के पारिवारिक मूल्यों से प्रेरणा ले और यदि समाज श्रीराम की समरसता की भावना से प्रेरणा ले, तो एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र की कल्पना साकार हो सकती है।

आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम केवल मंदिर बनाएं, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर राम का निर्माण करें। जब व्यक्ति के भीतर राम का जन्म होगा, तभी समाज में रामराज्य आएगा। राम केवल इतिहास नहीं हैं, राम केवल आस्था नहीं हैं, राम मानव सभ्यता के नैतिक भविष्य का नाम हैं। यही रामनवमी का वास्तविक संदेश है।

# भारत में महिलाओं के प्रति बदलने लगा है नजरिया

**अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च 1911 से पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना है।**

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने, बाधाओं को तोड़ने और सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज और राष्ट्र मजबूत होते है। यह समानता और अधिकारों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, जो महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक है। यह एक ऐसा दिन है जो महिलाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च 1911 से पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम है दान से लाभ है, जो उदारता, सहयोग और सामूहिक प्रगति के मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह अभियान इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं का समर्थन करना और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना सभी के लिए व्यापक सामाजिक और आर्थिक लाभ ला सकता है। इस अभियान का मूल विचार यह है कि जब महिलाएं शिक्षा, नेतृत्व, उद्यमिता, विज्ञान, कला और राजनीति जैसे क्षेत्रों में सशक्त होती हैं, तो इससे मजबूत समुदाय और साझा समृद्धि का निर्माण होता है। सहयोग और समान अवसरों को प्रोत्साहित करके, यह अभियान समाज में समावेशी विकास और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना चाहता है।

भारत में महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम इक्कीसवीं सदी की बात करे तो यहां की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही है। अब तो भारत की संसद ने भी महिलाओं के लिये लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कर दिया है। उससे आने वाले समय में भारत की राजनीति

में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जायेगी। देश में महिलाओं को अब सेना में भी महत्वपूर्ण पदो पर तैनात किया जाने लगा है। जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। महिलायें देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है तथा विकास में भी बराबर की भागीदार है। आज के युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे दो कदम आगे निकल चुकी है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान जीवन जीने का हक है। भारत में नारी को देवी के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही यहां महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है।

भारत में वर्षो से महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानून बने है। इसमें हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, क्रिस्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874,चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हर्रास्मेंट ऑफ वुमन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि। इसके अलावा 7 मई 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसम्बर 2015 को राज्य सभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अन्तर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक साल 2023 में भारत में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,05,861 अपराध दर्ज किए गए। इन अपराधों में बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, और अपहरण जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के सामने आए हैं।जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारी उदासीनता को दशार्ते हैं। इससे पहले 2022 में 4,45,256 मामले, 2021 में 4,28,278मामले 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर से पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिलीं। इसमें 16 हजार से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश राज्य से आए हैं। आंकड़े हैरान कर देने वाली हैं। क्योंकि आयोग में ये शिकायत गरिमा के अधिकार कैटेगरी के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,411 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 1,343, बिहार में 1,312 और मध्य प्रदेश में 1,165 इतने मामले दर्ज किए गए हैं।

2023 के 12 महीने बाद जारी किए गए इस रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे अपराध दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की यह रिपोर्ट महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता दिखाती है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में यौन उत्पीड़न के 805 मामले, साइबर अपराध के 605 मामले, पीछा करने की 472 मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ 409 शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल 2023 में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के 1,537 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत 8,540, घरेलू हिंसा के 6,274, दहेज उत्पीड़न के 4,797, छेड़छाड़ के 2,349,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के 1,618 मामले दर्ज किए गए।

2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2022 की तुलना में कम हुए हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30,864 मामले दर्ज किए गए थे। जबकि 2023 में यह संख्या घटकर 28,278 हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल 2022 के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब 30,864 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो 2014 के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किये हैं। आज भारत में महिलायें पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है।

हम एक तरफ महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देकर उन्हे आगे बढ़ा रहें है। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आये दिन हमें महिलाओं के साथ बलात्कार, दुर्व्यवहार होने की घटनाये सुनने को मिलती रहती है। ऐसी घटनाओं से महिला सशक्तिकरण के अभियान को धक्का लगता हैं।देश में महिलाओं के प्रति खराब होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम आदमी की भी है। हम सभी को आगे आकर महिला सुरक्षा की लड़ाई में महिलाओं का साथ देना होगा तभी देश की मातृ शक्ति सर उठा कर शान से चल सकेगीं। अब महिलाओं को समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इन परम्पराओं को बदलने का बीड़ा स्वयं महिलाओं को ही उठाना होगा। तभी समाज में उनके प्रति सोच बदल पायेगी।

अरुण मिश्रा

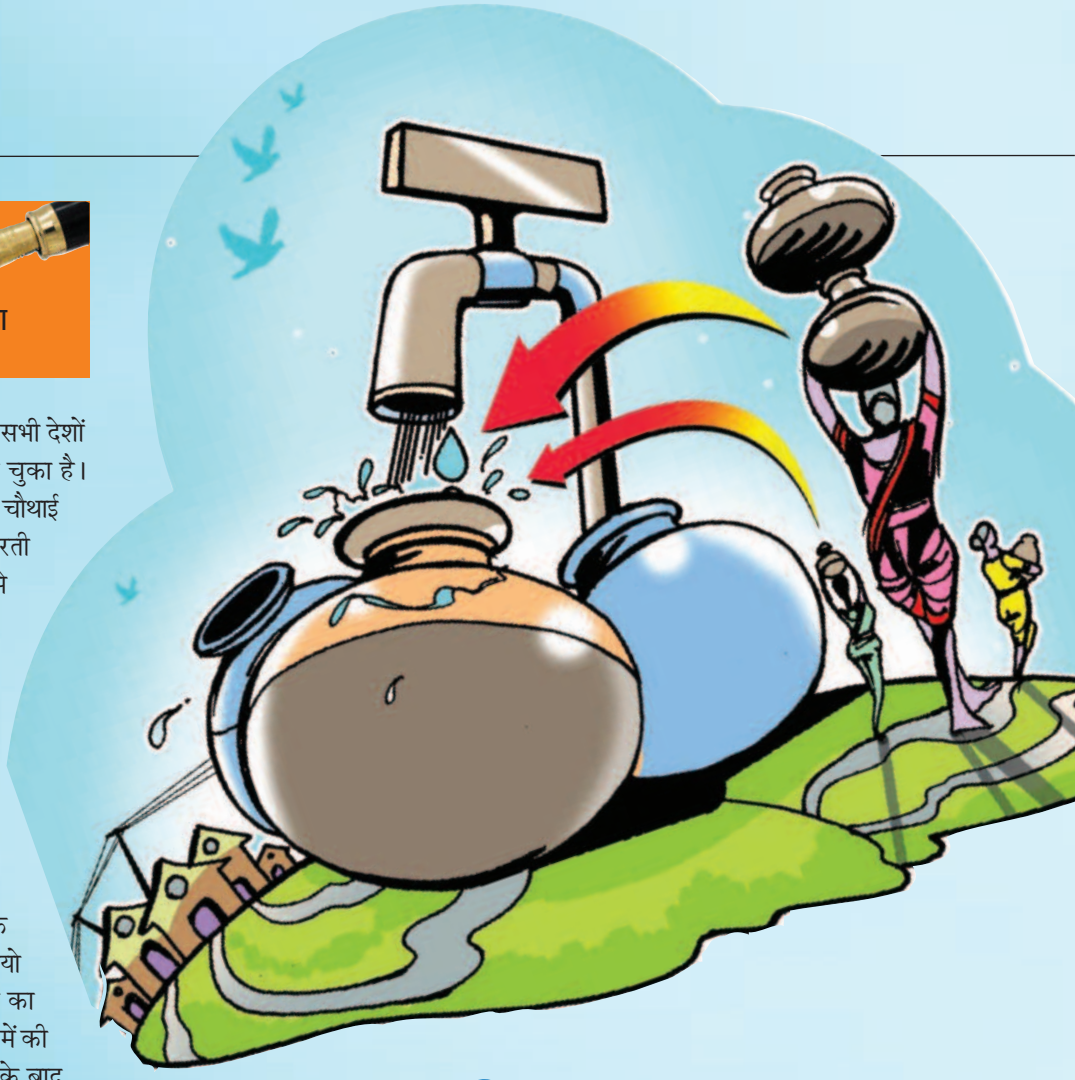

# हर बूंद की पुकार: जल संरक्षण ही समाधान

आल संकट दुनिया के लगभग सभी देशों की एक विकट समस्या बन चुका है। हालांकि पृथ्वी का करीब तीन चौथाई हिस्सा पानी से लबालब है लेकिन धरती पर मौजूद पानी के विशाल स्रोत में से महज एक-डेढ़ फीसदी पानी ही ऐसा है, जिसका उपयोग पेयजल या दैनिक क्रियाकलापों के लिए किया जाना संभव है। इसीलिए जल संरक्षण और रखरखाव को लेकर दुनियाभर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को 'विश्व जल दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1992 में रियो द जेनेरियो में आयोजित 'पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (यूएनसीईडी) में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की उसी घोषणा के बाद पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। सही मायनों में यह दिन जल के महत्व को जानने, समय रहते जल संरक्षण को लेकर सचेत होने तथा पानी बचाने का संकल्प लेने का दिन है।

विश्व जल दिवस 2026 की थीम है 'जल और लिंग' यह थीम लिंग और जल तक पहुंच के बीच के महत्वपूर्ण और प्रायः असमान संबंध को उजागर करती है तथा साथ ही इस बात पर भी जोर देती है कि वैश्विक जल संकट का सबसे अधिक बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है और उन्हें नेतृत्व एवं निर्णय लेने में शामिल किया जाना चाहिए। जल प्रबंधन एक लैंगिक मुद्दा है, जिसमें महिलाएं और लड़कियां अक्सर पानी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं और स्वच्छता सुविधाओं तक उनकी पहुंच सीमित होती है।

दुनियाभर में इस समय करीब दो अरब लोग ऐसे हैं, जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा और साफ पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण लाखों लोग बीमार होकर असमय काल का ग्रास बन जाते हैं। 'इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी' का कहना है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की कुल मात्रा में से मात्र तीन प्रतिशत पानी ही स्वच्छ बचा है और उसमें से भी करीब दो प्रतिशत पानी पहाड़ों व ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है जबकि शेष एक प्रतिशत पानी का उपयोग ही पेयजल, सिंचाई, कृषि तथा उद्योगों के लिए किया जाता है। बाकी पानी खारा होने अथवा अन्य कारणों की वजह से उपयोगी अथवा जीवनदायी नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में से इस एक प्रतिशत पानी में से भी करीब 95 फीसदी पानी भूमिगत जल के रूप में पृथ्वी की निचली परतों में उपलब्ध है और बाकी पानी पृथ्वी पर सतही जल के रूप में तालाबों, झीलों, नदियों अथवा नहरों में तथा मिट्टी में नमी के रूप में उपलब्ध है। स्पष्ट है कि पानी की हमारी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति भूमिगत जल से ही होती है लेकिन इस भूमिगत जल की मात्रा भी इतनी नहीं है कि इससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। वैसे भी जनसंख्या की रफ्तार तो तेजी से बढ़ रही है किन्तु भूमिगत जलस्तर बढ़ने के बजाय घट रहा है, ऐसे में पानी की कमी का संकट तो गहराना ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनियाभर में करीब तीन बिलियन लोगों के समक्ष पानी की समस्या मुंह बाये खड़ी है और विकासशील देशों में तो यह समस्या कुछ ज्यादा ही विकराल हो रही है, जहां करीब 95 फीसदी लोग इस समस्या को झेल रहे हैं।

विश्वभर में तेजी से उभरती पानी की कमी की समस्या भविष्य में खतरनाक रूप धारण कर सकती है, इसीलिए अधिकांश विशेषज्ञ आशंका जताने लगे हैं कि जिस प्रकार तेल के लिए खाड़ी युद्ध होते रहे हैं, जल संकट बरकरार रहने या और बढ़ते जाने के कारण आने वाले वर्षों में पानी के लिए भी विभिन्न देशों के बीच युद्ध लड़े जाएंगे और हो सकता है कि अगला विश्व युद्ध भी पानी के मुद्दे को लेकर ही लड़ा जाए। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान भी पूरी दुनिया को चेता चुके हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि आगामी वर्षों में पानी की कमी गंभीर संघर्ष का कारण बन सकती है। इसीलिए यह समय की सबसे बड़ी मांग है कि दुनियाभर में लोग बेशकीमती पानी की महत्ता को समय रहते समझें और इसके संरक्षण हर स्तर पर अपना योगदान दें। दरअसल पानी का अंधाधुध दोहन करने के साथ-साथ हमने नदी, तालाबों, झरनों इत्यादि अपने पारम्परिक जलस्त्रोतों को भी दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहा जाता रहा है कि भारत ऐसा देश है, जिसकी गोद में कभी हजारों नदियां खेलती थी लेकिन आज इन हजारों नदियों में से सैकड़ों ही शेष बची हैं और वे भी अच्छी हालत में नहीं हैं। हर गांव-मौहल्ले में कुएं और तालाब हुआ करते थे, जो अब पूरी तरह गायब हो गए हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि पृथ्वी की सतह पर उपयोग में आने लायक पानी की मात्रा वैसे ही बहुत कम है और यदि भूमिगत जल स्तर भी निरन्तर गिर रहा है तो हमारी पानी की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? इसके लिए हमें वर्षा के पानी पर आश्रित रहना पड़ता है किन्तु वर्षा के पानी का भी सही तरीके से संग्रहण नहीं हो पाने के कारण ही इसका भी समुचित उपयोग नहीं हो पाता। वर्षा के पानी का करीब 15 फीसद वाष्प के रूप में उड़ जाता है और करीब 40 फीसद पानी नदियों में बह जाता है जबकि शेष पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे थोड़ा बहुत भूमिगत जल स्तर बढ़ता है और मिट्टी में नमी की मात्रा में कुछ बढ़ोतरी होती है। इसलिए यदि हम वर्षा के पानी का संरक्षण किए जाने की ओर खास ध्यान दें तो व्यर्थ बहकर नदियों में जाने वाले पानी का संरक्षण कर उससे पानी की कमी की पूर्ति आसानी से की जा सकती है और इस तरह जल संकट से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

पानी को मानव की मूलभूत आवश्यकता, अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर व अति विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन मानते हुए 1987 में जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास के लिए 'राष्ट्रीय जल नीति' घोषित की गई थी। इसके क्रियान्वयन के मामले में और तेजी लाने की जरूरत है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करते समय कहा गया था कि देश में उपलब्ध जल संसाधनों के विकास, संरक्षण, समुचित उपयोग एवं प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। देश में जल संकट के विकराल रूप धारण करते जाने के पीछे जनसंख्या विस्फोट के साथ-साथ पानी की उपलब्धता में हो रही कमी तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा पानी का दुरूपयोग, कुप्रबंधन एवं दूषित होता पेयजल आदि और भी कई ऐसी वजहें हैं, जो समस्या को विकराल बना रही हैं। हमें यह भली-भांति समझना होगा कि पानी प्रकृति की अमूल्य देन है और हम स्वयं पानी का निर्माण नहीं कर सकते। विकराल होते जल संकट का समाधान तभी संभव है, जब आमजन में इस दिशा में जागरूकता पैदा करने के अपेक्षित प्रयास किए जाएं तथा सरकारी प्रयासों के साथ-साथ हर नागरिक भी पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए अपने-अपने स्तर पर प्रयास करे।

# बदलती जीवनशैली और गलत खान पान से बिगड़ रहा बच्चों का स्वास्थ्य

भारत लंबे समय तक कुपोषण और अल्पपोषण की समस्या से जूझता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में एक नई स्वास्थ्य चुनौती तेजी से उभर कर सामने आई है–चाइल्डहुड ओबेसिटी। यह समस्या धीरे-धीरे फैल रही है और इसके प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देते हैं, इसलिए इसे 'साइलेंट पैन्डेमिक' कहा जाता है। बदलती जीवनशैली, शहरीकरण, तकनीकी प्रगति और भोजन की आदतों में आए परिवर्तन ने बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। पहले जहाँ भारतीय बच्चों में कुपोषण प्रमुख समस्या थी, वहीं अब कई बच्चे अधिक वजन और मोटापे से भी प्रभावित हो रहे हैं। यह स्थिति भारत के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि देश की बड़ी आबादी युवा है और बच्चों का स्वास्थ्य सीधे भविष्य की मानव पूंजी से

डॉ. मुकुल शर्मा

जुड़ा हुआ है। भारत में बाल मोटापे की समस्या शहरी क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन अब यह धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लगी है। इसके पीछे कई सामाजिक और व्यवहारिक कारण कार्य कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण तेजी से बढ़ता शहरीकरण और उससे जुड़ी जीवनशैली है। शहरों में बच्चों के पास खेलने के लिए पर्याप्त खुले मैदान या सुरक्षित स्थान नहीं होते। अपार्टमेंट संस्कृति, ट्रैफिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण बच्चे बाहर खेलने के बजाय घर के अंदर समय बिताने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और वे अधिकतर समय बैठकर पढ़ाई करने, टीवी देखने या मोबाइल फोन का उपयोग करने में बिताते हैं। यह निष्क्रिय जीवनशैली मोटापे के प्रमुख कारणों में से एक बन चुकी है।

भोजन की आदतों में आया परिवर्तन भी बाल मोटापे की समस्या को बढ़ा रहा है। पारंपरिक भारतीय आहार, जिसमें दाल, सब्ज़ियाँ, अनाज और फल प्रमुख थे, धीरे-धीरे फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से प्रतिस्थापित हो रहा है। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स और शर्करा युक्त पेय पदार्थ बच्चों के आहार का सामान्य हिस्सा बन गए हैं। ये खाद्य पदार्थ कैलोरी में अधिक और पोषण में कम होते हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त वसा का संचय होने लगता है। साथ

ही, बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनियों और फास्ट फूड उद्योग के विस्तार ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है।

मीडिया और विज्ञापन भी बच्चों की भोजन संबंधी पसंद को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जंक फूड के आकर्षक विज्ञापन बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित करते हैं। कई कंपनियाँ कार्टून चरित्रों और रंगीन पैकेजिंग का उपयोग करके बच्चों को लक्षित करती हैं। परिणामस्वरूप बच्चे पौष्टिक भोजन के बजाय अधिकतर जंक फूड की मांग करते हैं। इसके अलावा स्कूलों के आसपास फास्ट फूड की दुकानों की उपलब्धता भी इस समस्या को बढ़ाती है। परिवार और सामाजिक परिवेश भी बच्चों की जीवनशैली को प्रभावित करते हैं। आधुनिक जीवन की व्यस्तता के कारण माता-पिता के पास बच्चों के लिए घर का बना पौष्टिक भोजन तैयार करने का समय कम होता है। कई बार माता-पिता बच्चों को खुश करने या पुरस्कार देने के लिए उन्हें जंक फूड देते हैं। इससे धीरे-धीरे बच्चों में अस्वस्थ भोजन की आदत विकसित हो जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि परिवार में मोटापा या मधुमेह जैसी समस्याएँ मौजूद हों, तो बच्चों में भी मोटापे की संभावना बढ़ जाती है।

व्यवहारिक स्तर पर भी कई ऐसे कारक हैं जो बाल मोटापे को बढ़ावा देते हैं। शारीरिक गतिविधि की कमी सबसे प्रमुख कारण है। बच्चों का अधिकांश समय स्कूल, कोचिंग और होमवर्क में बीतता है, जिससे खेलकूद के लिए समय कम बचता है। इसके अलावा डिजिटल तकनीक के प्रसार ने बच्चों के जीवन में स्क्रीन टाइम को काफी बढ़ा दिया है। मोबाइल फोन, वीडियो गेम, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के कारण बच्चे लंबे समय तक बैठे रहते हैं। यह निष्क्रिय व्यवहार ऊर्जा खर्च को कम करता है और मोटापे का जोखिम बढ़ाता है। अनियमित भोजन की आदतें भी मोटापे की समस्या को बढ़ाती हैं। कई बच्चे नाश्ता छोड़ देते हैं, देर रात भोजन करते हैं या दिनभर में बार-बार स्नैक्स खाते रहते हैं। इन आदतों से शरीर का चयापचय प्रभावित होता है और वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही पर्याप्त नींद की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। देर रात तक मोबाइल या टीवी देखने के कारण बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, जिससे भूख और तृप्ति से जुड़े हार्मोन प्रभावित होते हैं और अधिक खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

प्रारंभिक जीवन से जुड़े कुछ कारक भी बाल मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे कि शिशु अवस्था में स्तनपान की कमी, मातृ मोटापा और गर्भावस्था के दौरान असंतुलित पोषण भविष्य में बच्चे के चयापचय को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों के कारण बच्चे में मोटापे का जोखिम बढ़ जाता है।

बाल मोटापे के प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी होते हैं। सबसे पहले, यह कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देता है। मोटापे से ग्रस्त बच्चों में टाइप-2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फैटी लिवर जैसी समस्याएँ कम उम्र में ही विकसित हो सकती हैं। पहले ये बीमारियाँ मुख्य रूप से वयस्कों में देखी जाती थीं, लेकिन अब बच्चों और किशोरों में भी इनके मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मोटापा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अधिक वजन वाले बच्चों को अक्सर साथियों द्वारा उपहास या भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है। इससे अवसाद, चिंता और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार मोटापा बच्चों के समग्र विकास को बाधित करता है।

बाल मोटापे का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव यह है कि यह वयस्कता में भी बना रह सकता है। कई शोध बताते हैं कि मोटापे से ग्रस्त बच्चे बड़े होकर भी मोटापे से पीड़ित रहते हैं। इससे जीवन के बाद के वर्षों में हृदय रोग, कैंसर और अन्य गैर-संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार बाल मोटापा भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का संकेत भी है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समस्या गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। मोटापे से संबंधित बीमारियों के उपचार पर स्वास्थ्य प्रणाली का खर्च बढ़ सकता है। इसके साथ ही कार्य क्षमता और उत्पादकता में कमी आने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ेगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

मानव पूंजी के दृष्टिकोण से भी बाल मोटापा चिंता का विषय है। बच्चों का स्वास्थ्य उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है, जो आगे चलकर उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि बड़ी संख्या में बच्चे मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों से प्रभावित होते हैं, तो यह देश की दीर्घकालिक विकास क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।

इस समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले, पोषण शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि बच्चे और उनके माता-पिता स्वस्थ भोजन के महत्व को समझ सकें। स्कूलों में नियमित खेल गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर नियंत्रण और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सरकार को खाद्य उद्योग के नियमन के लिए भी कदम उठाने चाहिए। जंक फूड के विज्ञापनों पर नियंत्रण, खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट पोषण लेबलिंग और उच्च चीनी व वसा वाले उत्पादों पर कर जैसे उपाय उपयोगी हो सकते हैं। शहरी नियोजन में भी बच्चों के लिए पार्क, खेल मैदान और साइकिल ट्रैक जैसे सार्वजनिक स्थानों का विकास किया जाना चाहिए।

अंततः परिवार और समुदाय की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता-पिता को बच्चों को संतुलित आहार देने, स्क्रीन टाइम सीमित करने और खेलकूद के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवनशैली को परिवार और समाज दोनों स्तरों पर प्रोत्साहित करना होगा।

# भारतीय सिनेमा में तेजी से बढ़ता वेब सीरीज का चलन

उज्जवल रस्तौगी

पिछले एक दशक में भारतीय मनोरंजन जगत में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जहाँ पहले सिनेमा हॉल और टेलीविजन धारावाहिक मनोरंजन के प्रमुख माध्यम थे, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज ने दर्शकों की पसंद और देखने की आदतों को पूरी तरह बदल दिया है। स्मार्टफोन, सस्ती इंटरनेट सेवाएँ और ओटीटी प्लेटफॉर्म के विस्तार ने वेब सीरीज को घर-घर तक पहुँचा दिया है।

भारत में वेब सीरीज की लोकप्रियता विशेष रूप से 2015 के बाद तेजी से बढ़ी है। डिजिटल

प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिस्नी, हॉट स्टार, जी-5, और सोनी लिव ने भारतीय बाजार में प्रवेश कर दर्शकों को वैश्विक स्तर की सामग्री उपलब्ध कराई। इन प्लेटफॉर्म्स ने न केवल विदेशी सीरीज को लोकप्रिय बनाया बल्कि भारतीय कहानियों को भी नए अंदाज में प्रस्तुत किया।

कोविड-19 महामारी के दौरान जब सिनेमा हॉल बंद थे, तब वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरंजन का प्रमुख माध्यम बन गए। इस अवधि में डिजिटल सामग्री की खपत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसने वेब सीरीज को स्थायी रूप से भारतीय मनोरंजन उद्योग का अहम हिस्सा बना दिया।

वेब सीरीज की लोकप्रियता के कारण विषयों की विविधता भी है। वेब सीरीज में विषयों में सामाजिक मुद्दे, राजनीति, अपराध, रोमांस, ऐतिहासिक कथाएँ, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और यथार्थवादी ड्रामा—सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। सिनेमा की तुलना में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रचनाकारों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे

वे संवेदनशील और जटिल विषयों को बिना अधिक कटौती के प्रस्तुत कर पाते हैं। फिल्में आमतौर पर दो से तीन घंटे की होती हैं, जबकि वेब सीरीज में कई एपिसोड होते हैं। इससे पात्रों का गहन विकास और कहानी की विस्तृत प्रस्तुति संभव हो पाती है। दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय, किसी भी स्थान पर वेब सीरीज देख सकते हैं। यह लचीलापन युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है।

## भारतीय प्रमुख वेब सीरीज के नाम

भारतीय वेब सीरीज ने न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। कुछ प्रमुख और चर्चित वेब सीरीज में सैक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, दॉ फैमिली मैन, पंचायत, स्कैम-1992, एस्पीरेंट्स, दिल्ली क्राइम्स, आदि हैं। इनमें सैक्रेड गेम्स, भारतीय ओटीटी जगत की पहली बड़ी सफल सीरीज मानी जाती है। अपराध और राजनीति पर आधारित इस सीरीज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त की। इसकी कहानी, अभिनय और निर्देशन ने वेब कंटेंट की गुणवत्ता को नई ऊँचाई दी। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित यह अपराध-ड्रामा सीरीज अपने दमदार संवादों और किरदारों के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुई। इसमें सत्ता, राजनीति और अपराध का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है।दॉ फैमिली मैन सीरीज एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति की कहानी है जो गुप्तचर एजेंसी में काम करता है। इसमें पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन की चुनौती को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वहीं पंचायत ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित यह हल्की-फुल्की लेकिन प्रभावशाली सीरीज दर्शकों के दिलों को छू गई। इसमें गाँव की राजनीति, सामाजिक रिश्तों और हास्य का सुंदर चित्रण है। इसी तरह के अन्य बेव सीरीज 1992 के शेयर बाजार घोटाले पर आधारित है। वही एस्पीरेंटयूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की कहानी पर आधारित यह सीरीज युवाओं के संघर्ष और सपनों को दर्शाती है। इसकी सादगी और भावनात्मक गहराई ने इसे लोकप्रिय बनाया।

आज के समय में वेब सीरीज के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक सिनेमा पर भी असर डाला है। अब फिल्म निमार्ता और अभिनेता भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं। कई बड़े सितारों ने वेब सीरीज में काम किया है, जिससे इस माध्यम की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हालाँकि, कुछ वेब सीरीज में अत्यधिक हिंसा, अश्लीलता या अपशब्दों के प्रयोग को लेकर आलोचना भी होती रही है। इस कारण डिजिटल सामग्री के लिए नियमन और दिशा निदेर्शों की मांग उठने लगी है। इसके सबके बावजूद भारतीय वेब सीरीज का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। 5 जी तकनीक, स्मार्ट टीवी और डिजिटल भुगतान के विस्तार से ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुँच और बढ़ेगी। आने वाले समय में और अधिक प्रयोगात्मक, अंतरराष्ट्रीय स्तर की और बहुभाषीय सामग्री देखने को मिलेगी।

# वर्ल्ड कप के ये 5 क्रिकेटर रहे हीरो

**टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की न्यूजीलैंड पर जीत से भारतीयों की ख्वाहिश पूरी हुई। टी20 विश्व कप में अपने खिताब को बरकरार रखने वाली सूर्य कुमार यादव की सेना घरेलू मैदान पर खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। भारत ने 100,000 उत्साही और तकरीबन पूरी तरह से नीले रंग की जर्सी पहने समर्थकों के सामने न्यूजीलैंड को रनों की बौछार से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम तकरीबन एकतरफा मुकाबले में 96 रनों से हार गई। इस टीम के हीरो रहे संजू सैमसन , अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह और कप्तान सूर्य कुमार यादव। मंडे मोटिवेशन में जानते हैं इनकी प्रेरक कहानियां, जो हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा हो सकती हैं।**

महमूद रजा
बिजनौर

## ईशान किशनः कभी हार नहीं मानने वाला हीरो

**भारतीय** क्रिकेट में प्रतिभाशाली खिलाड़ी कोई असामान्य बात नहीं हैं। लेकिन ईशान किशन के सफर में जो बात अनोखी है, वह यह है कि इसकी जड़ें झारखंड में हैं। एमएस धोनी के बाद इस युवा खिलाड़ी ने विकेटकीपर बल्लेबाज बनने का फैसला किया। बाएं हाथ के सलामी और विस्फोटक बल्लेबाज किशन पहली बार खबरों में तब आए, जब 2016 में उन्हें ढाका में आयोजित अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी सौंपी गई।

ईशान किशन ने मार्च, 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया। उन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज वनडे दोहरा शतक 210 (131 गेंदों में) जड़कर सुर्खियां बटोरीं। ऐसे मौके भी आए, जब ईशान किशन को मानसिक सेहत को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि वो टीम से बाहर भी हो गए। ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की। अब वह टी20 और वनडे खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी 216 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 25 बॉल पर 54 रन बनाए।

## संजू सैमसनः 1 महीने में ही ऐसा कमबैक तो नहीं देखा

**संजू सैमसन** को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का प्लेयर ऑफ द टूनार्मेंट चुना गया। इसी साल 31 जनवरी, 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में बेहद निराश हो गए थे, जब टीम मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि संजू की जगह अब शतक लगाने वाले ईशान किशन को विकेटकीपिंग का जिम्मा दे दिया गया। उस मैच में भी संजू सैमसन के बल्ले से महज 6 रन ही निकले थे। टी20 इंटरनेशनल में लगातार 11वीं पारी में संजू सैमसन अर्धशतक लगाने से चूक गए थे।

आईसीसी वर्ल्ड कप के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि जिस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के काबिल ना समझा जाए वो प्लेयर ऑफ द टूनार्मेंट बनकर निकले। आज वह भारत की जीत के सबसे बड़े नायक हैं। टी-20 वर्ल्ड कप के तीनों नॉकआउट मुकाबले में उन्होंने एक से बढ़कर एक पारी खेली।

संजू सैमसन ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे कामयाब कमबैक में काउंट किया जा सकता है। संजू सैमसन ने पहले वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन की नाबाद पारी खेली और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। फिर उन्होंने वानखेड़े में 42 गेंद में 89 रन की पारी खेलकर ये तय किया कि भारतीय टीम फाइनल का हिस्सा बनने जा रही है। इसके बाद अहमदाबाद में संजू ने 89 रन की पारी खेलकर तय किया कि टी-20 वर्ल्ड कप का ताज भारत के पास ही रहेगा।

**मुझे पता था कि दोबारा बेहतर होने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद मैं टूट गया था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा सपना बिखर गया है। लेकिन शायद ईश्वर के पास कोई और प्लान था।**

**-: संजू सैमसन**

## सूर्यकुमार यादव : टीम इंडिया के सूरज बने

टी-20 वर्ल्ड कप में फाइनल के दौरान जैसे ही टीम इंडिया ने मैच अपने नाम किया, वैसे ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पिच की मिट्टी अपने माथे लगा ली। यूपी के गाजीपुर जिले से नाता रखने वाले और मुंबई में पले-बढ़े सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के एक आक्रामक मध्य-क्रम के बल्लेबाज हैं। सूर्या को स्कूप शॉट खेलने का एक्सपर्ट और टी-20 का 'मिस्टर 360' कहा जाता है। उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है।

सूर्या कहते रहे हैं-'मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था'। सूर्यकुमार यादव, जिन्हें स्काई के नाम से भी जाना जाता है, हर बार जब भी मैदान पर उतरते हैं, परंपराओं को चुनौती देते हैं और गेंदबाजों को परेशान कर देते हैं।

SKY ने मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और छक्का लगाकर अपना पहला अर्धशतक पूरा किया था। सूर्या 2022 टी-20 विश्व कप में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 2022 का आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। टी-20 कप्तान बनने के बाद से सूर्यकुमार यादव ने भारत को श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विदेशी सीरीज में जीत दिलाई है। उनकी अगुवाई में इंग्लैंड को घरेलू मैदान पर भी करारी शिकस्त मिली है। उन्होंने अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे युवाओं को निडर होकर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि, कप्तानी संभालने के बाद से उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन पहले के मुकाबले उतना बेहतर नहीं रहा है। उन्होंने साथी खिलाड़ियों का मनोबल जरूर बढ़ाया। उन्होंने अपनी कप्तानी में यह टीम इंडिया को वर्ल्ड कप विजेता बनाया।

## जसप्रीत बुमराहः दबाव में भी उभरे

**भारतीय** टीम के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जब अहमदाबाद में टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के चार बल्लेबाजों का आउट किया, तभी भारत की जीत तय हो गई थी। जसप्रीत बुमराह ने इस जीत को 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में मिली हार की भड़ास निकालने के रूप में लिया। उस साल भारत को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। अब टीम ने इसी मैदान पर टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम को डेथ ओवरों के लिए एक दमदार गेंदबाज की सख्त जरूरत थी, ऐसे में जसप्रीत बुमराह इंडियन प्रीमियर लीग के जरिए उभरे और क्रिकेट जगत के लिए वरदान साबित हुए। गुजरात के इस दुबले-पतले तेज गेंदबाज ने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी में लसिथ मलिंगा के सहायक के रूप में रहते हुए सटीक यॉर्कर फेंकने की कला में महारत हासिल कर ली और सीमित ओवरों के फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए।

**यह जीत बेहद खास है, क्योंकि मैंने अपने होम ग्राउंड पर पहले भी एक फाइनल खेला था। हालांकि, तब हम जीत नहीं पाए थे। आज जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता था कि विकेट काफी सपाट है, इसलिए मुझे अपना पूरा अनुभव इस्तेमाल करना था। इस टूर्नामेंट से पहले मैं ऐसे दौर में था, जहां मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं खुद पर ज्यादा दबाव डाल रहा हूं। -:जसप्रीत बुमराह**

## अभिषेक शर्माः लय बिगड़ी, मगर हौसला कायम रहा

**टी-20** वर्ल्ड कप के फाइनल में अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने 247.61 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों पर 52 रन बनाए। अमृतसर, पंजाब के अभिषेक शर्मा ने तेज और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, घरेलू क्रिकेट में पंजाब और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए टॉप-3 में आसानी से अपनी जगह बना ली। वह एक उपयोगी बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं जो अपनी बैकस्पिनिंग लेगकटर से बल्लेबाजों को चौंका सकते हैं।

2015-16 में विजय मर्चेंट घरेलू अंडर-16 टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में (जहां उन्होंने सात मैचों में अविश्वसनीय 1200 रन बनाए)। अगले सीजन में भारत के कप्तान के रूप में उन्होंने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। वह 2018 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का भी अभिन्न हिस्सा थे, जहां उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 50 रन बनाए और 11 रन देकर 2 विकेट लिए।

दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 2018 की नीलामी में खरीदा और उन्होंने अपने पहले ही आईपीएल मैच में 19 गेंदों में 46 रन बनाए, लेकिन उसके बाद कुछ सीजन तक उनकी लय बिगड़ती रही। 2022 में, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपने चौथे सीजन में अभिषेक ने 133 के स्ट्राइक रेट से 426 रन बनाए। सबसे यादगार पल वह था जब उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मैच में राशिद खान की 15 गेंदों में 34 रन बनाए।

**SHANTI NATH MANUFACTURERS**
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

**CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.**
VCB PANEL, CRP,
TRANSFORMER, RMU ETC

CG

**SECURE METERS LTD.**
ENERGY METER
(POSTPAID/PREPAID/
SOLAR/ABT)

SECURE

**MITSUBISHI ELECTRIC**
MCB/MCCB/ACB/
CONTRACTOR/DB

MITSUBISHI
ELECTRIC

# Kumar Enterprises

GF-150 | DURGA TOWER | RDC | RAJ NAGAR | GHAZIABAD (UP) - 201001
TEL. : 0120-4137613 | EMAIL : ke.ghaziabad@gmail.com
SANJEEV KUMAR 9268566079